राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 29 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-294 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सैन्य ताकत ब्रह्मोस-बराक मिसाइलों से लैस,75 फीसदी उपकरण स्वदेशी

नया योद्धा आईएनएस विंध्यगिरि नेवी में हुआ शामिल

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17ए का सातवां और आखिरी युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरि सौंप दिया गया है। शुक्रवार को कोलकाता के गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में इसकी डिलीवरी हुई। इसके साथ ही नीलगिरि क्लास के सभी सात युद्धपोत नौसेना को मिल गए हैं। करीब 45 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 23 महीने में सभी युद्धपोत सौंपे गए हैं। आईएनएस विंध्यगिरि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और बराक-8 एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है। इसमें स्टील्थ तकनीक, आधुनिक रडार और अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली लगाई गई है। इससे यह दुश्मन के जहाजों, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों से मुकाबला कर सकता है।



75 फीसदी उपकरण स्वदेशी हजारों लोगों को मिला रोजगार

युद्धपोत के करीब 75 फीसदी उपकरण और तकनीक स्वदेशी हैं। इसके निर्माण में 200 से ज्यादा निर्माण कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट से करीब 4 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। इसकी लंबाई 149 मीटर और वजन 6,670 टन है। इसमें 225 नौसैनिकों के रहने और हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधा है। प्रोजेक्ट 17ए के बाद नौसेना अब प्रोजेक्ट 17बी के तहत सात अगली पीढ़ी के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शिपयार्ड के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना का अनुबंध 2028 में होने की संभावना है।

अफगानिस्तान में स्कूल के पास धमाका, 7 बच्चों की हुई मौत

- 100 घायल,गोदाम में डायनामाइट रखा था इसी से विस्फोट हुआ



काबुल (एजेंसी)। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में शनिवार को एक स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। इसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके पहले 6 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई थी। धमाका स्कूल के बगल में बने विस्फोटक (डायनामाइट) रखने के गोदाम में हुआ। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि गोदाम में लापरवाही के चलते विस्फोट हुआ। कुनार के सूचना एवं संस्कृति विभाग के निदेशक ने बताया कि गोदाम में खनन कंपनियों के विस्फोटक रखे हुए थे। घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायलों में से 15 का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रावण 'मैं और मेरा' में अटका रहा

राम सबके हो गए

मोहन भागवत बोले-यही अहंकार और करुणा के बीच का फर्क

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि रावण अहंकारी था, जबकि राम करुणा के प्रतीक थे। रावण मैं और मेरा से आगे नहीं जा पाया। जबकि राम सबके हो गए। यही अहंकार और करुणा के बीच का फर्क है। भागवत दिल्ली में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब 'करुणानायक राम' के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। समारोह में भूटान के शाही परिवार की राजमाता और राजकुमारी भी मौजूद थीं। देश और दुनिया की लगभग हर समस्या की जड़ करुणा का अभाव है। चाहे समस्या वर्तमान की हो, अतीत की या भविष्य की, उसका समाधान करुणा और संवेदनशीलता से ही संभव है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के विचार करुणा का वैश्वीकरण की आज पूरी दुनिया को जरूरत है। करुणा केवल किसी एक व्यक्ति या देश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरी मानवता में होनी चाहिए।



राम और रावण के बीच असली अंतर

रावण अहंकार का प्रतीक था, जबकि भगवान राम करुणा के प्रतीक थे। रावण को अपने बल, ज्ञान और साम्राज्य पर घमंड था। वह मैं और मेरा से आगे नहीं सोच पाया, जबकि राम दूसरों के प्रति दया और संवेदना रखते थे। लोगों का रंग, रूप और व्यवहार भले ही अलग-अलग हो, लेकिन भीतर से सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं। यही एकता संसार का स्थायी सत्य है। इसी भावना को समझना ही करुणा का आधार है। धर्म का शाश्वत स्वरूप करुणा है। महान व्यक्तियों के जीवन को केवल उनके कामों से नहीं, बल्कि उनके विचारों और दूसरों के प्रति उनके व्यवहार से भी समझना चाहिए। दुनिया में होने वाले युद्ध और टकराव की एक बड़ी वजह लोगों की संकीर्ण सोच और केवल अपने हितों को प्राथमिकता देना है। मानव जाति अकेले सुखी नहीं रह सकती। जब तक पूरा संसार और पर्यावरण स्वस्थ व खुशहाल नहीं होगा, तब तक सुख हासिल नहीं कर सकता।

कांग्रेस नाराज, परिसीमन बिल का करेगी विरोध

- खरगे बोले-पीएम चीन की तरह सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि परिसीमन लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा पूरी सत्ता हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। यह हमें स्वीकार नहीं है। जैसे चीन में हाथ उठाते हैं, वैसे ही भारत में करना चाहते हैं कि हाथ उठाकर बहुमत लेकर लोकतंत्र खत्म करेंगे। परिसीमन बिल को लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने शनिवार को सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग की। खड़गे बोले- नए परिसीमन से एससी-एसटी की सीटें बढ़ना चाहिए। सरकार जो बिल ला रही है, उसमें इसका प्रावधान नहीं है।



850 सीटें बढ़ेंगी तो देश को बड़ा नुकसान होगा

खड़गे ने कहा- आज जब उनको महसूस हो रहा है कि नंबर आ गए, तब यह बिल ला रहे हैं। चंद लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि 850 सीटें बढ़ जाएंगी तो देश को बड़ा नुकसान होगा। लोकतंत्र खत्म होगा। 850 सीटें करके यह अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते हैं।

एआई से 2027 में कोरोना से ज्यादा मौतों का खतरा

यह बेकाबू हो सकता है, अपराधियों के हाथ लग सकते हैं जानलेवा वायरस

बर्कले (एजेंसी)। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई कोरोना से भी बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। जीपीटी-5 की सुरक्षा जांच कर चुके वैज्ञानिक निकोला युर्कोविच ने एआई के बेकाबू होने की आशंका जताई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एआई की मदद से अपराधियों के हाथ जैविक हथियार बनाने की तकनीक लग सकती है। इससे 2027 में लाखों मौतें हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी से दुनिया भर में 71 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज हुई थीं। हालांकि, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि असल संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। निकोला ने ऑनलाइन बैंकिंग ठप होने की भी आशंका जताई है। उन्होंने लोगों से घर में 14 दिन का राशन-पानी और नकदी रखने को कहा है। निकोला के मुताबिक एआई पर इंसानों का कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है।



- 2030 के अंत तक इंसानियत खत्म होने का खतरा- युर्कोविच के मुताबिक एआई के विकास की रफ्तार नहीं रुकी तो 2030 के अंत तक इंसानियत के खत्म होने या एआई से कंट्रोल खोने का खतरा 50 फीसदी है। अगर इससे बच भी गए तो अगले 10 साल में मौजूदा ज्यादातर नौकरियां खत्म हो सकती हैं। विशेषज्ञों को डर है कि एआई भविष्य में खुद नए हथियार बना सकता है। वह ड्रोन और रोबोट की मदद से जरूरी ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। एआई का इस्तेमाल खतरनाक जैविक हथियार बनाने में भी हो सकता है।

बिसलेरी के पानी में बैक्टीरिया मिला, बंगाल का सेंपल फेल



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बिसलेरी के पानी के सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है। एजेंसी के मुताबिक, प्राथमिक और रेफरल दोनों लैब में इसकी पुष्टि हुई। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सीवेज के पानी या गंदे पाइपों के जरिए पीने के पानी में पहुंच सकता है। इससे पहले गोवा में बिसलेरी के पानी के सैंपल में कैंसर से जुड़े केमिकल ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मिले थे। तब भी कंपनी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी गई थी।

कहा-जंग एक साथ जमीन-समुद्र-आसमान में लड़ी जाएगी

ऑपरेशन सिंदूर भविष्य के युद्ध का टेम्प्लेटः सीडीएस

- एनएस राजा सुब्रमणि बोले-जो इनको साध लेगा,वही जीतेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ही भविष्य के युद्ध का टेम्प्लेट है। उसी तरह के युद्ध अब आगे लड़े जाएंगे, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ, एक योजना पर, एक समय पर काम करेंगी। सीडीएस ने दिल्ली में कहा कि अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध जमीन, आसमान, समुद्र, आकाश, संचार तंत्र और दिमाग सब जगह एक साथ लड़ा जाएगा। जो देश इन सबको एक साथ जोड़कर सबसे तेज चलेगा, वही जीतेगा। उन्होंने कहा कि अब अकेले हथियार किसी काम के नहीं हैं। जरूरत जुड़ी हुई व्यवस्था की है। एक सैटेलाइट निशाना देखेगा, दूसरा सिस्टम उसे पक्का करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम जानकारी देगा और जमीन पर, हवा में, समुद्र में या समुद्र के नीचे, कोई भी हथियार आखिर में वार करेगा। युद्ध का चरित्र मुख्य रूप से बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में बढ़त सिर्फ अस्थायी है, हमें लगातार सुधार करते रहना होगा। आज जो हथियार सबसे आधुनिक है, वो कल पुराना हो जाएगा। जो देश टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा, वो पीछे रह जाएगा।





युद्ध और शांति की लाइन मिट गई है

युद्ध और शांति के बीच का फर्क धुंधला हो रहा है, हम लगातार टकराव की स्थिति में हैं। दुश्मन हम पर धीरे-धीरे, चालाकी से कॉग्निटिव वॉरफेयर (दिमागी युद्ध) थोप रहा है। ये युद्ध बिना गोली के चल रहा है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम युद्ध में हैं। हमें अपना टेम्प्लेट बनाना होगा, किसी के बताए हुए टेम्प्लेट को नहीं देखना है। मतलब- अमेरिका, चीन, रूस का तरीका भारत पर लागू नहीं होगा। भारत की जियोग्राफी, दुश्मन, बजट, खतरे सब अलग हैं। इसलिए भारत का अपना युद्ध का मॉडल होना चाहिए। जनरल सुब्रमणि ने कहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान की स्पेस में क्षमता बढ़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि तुर्किये भी पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दे सकता है।

विस्तार महिला आरक्षित सीटें भी चुनेगा,सुप्रीम जज होंगे अध्यक्ष

कहां, कितनी सीटें बढ़ेंगी,परिसीमन आयोग करेगा तय

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है। किस राज्य में कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, यह तय करने की जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की होगी। आयोग महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षित सीटों की पहचान भी करेगा। आयोग में तीन मुख्य सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। इसके अलावा हर राज्य से 10 सहयोगी सदस्य नामित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अन्य दो सदस्य होंगे। मेघालय और नगालैंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त की जगह राज्यपाल की ओर से नामित व्यक्ति यह जिम्मेदारी निभाएगा। आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार इसे बढ़ा भी सकेगी।

देश के हर राज्य से 10 सहयोगी सदस्य मिलेंगे,है तैयारी



- **हर राज्य से 5 सांसद और 5 विधायक सहयोगी सदस्य**- प्रत्येक राज्य से पांच लोकसभा सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करेंगे। पांच विधायकों को संबंधित राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नामित करेंगे। ये सहयोगी सदस्य आयोग की बैठकों और चर्चाओं में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन उन्हें मतदान करने या आयोग के फैसलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। परिसीमन की प्रक्रिया के लिए आयोग रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त, सर्वेयर जनरल और अन्य सरकारी अधिकारियों की सहायता ले सकेगा। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकेगा।

अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव

संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे। राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मौजूदा सीटों के मुकाबले 50 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे लोकसभा में राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी का अनुपात मोटे तौर पर बना रहेगा।

महिलाओं को 15 साल के लिए मिलेगा आरक्षण

महिलाओं के लिए आरक्षण 2023 के संविधान संशोधन के लागू होने की तारीख से 15 साल तक रहेगा। संसद कानून बनाकर इसकी अवधि बढ़ा सकेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें संबंधित वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर तय की जाएंगी। आरक्षित सीटों का रोटेशन किस प्राधिकरण और किस तरीके से होगा, यह संसद तय करेगी।

उत्तराखंड के रिखणीखाल में भीषण सड़क हादसा

छह महिलाओं समेत 7 की मौत

पौड़ी (एजेंसी)। उत्तराखंड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। पौड़ी जिले के कोटद्वार के रिखणीखाल ब्लॉक में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वालों में एक ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं शामिल थी। जो कि बैंक से कुछ काम निपटाकर लौट रही थीं। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है। हादसा कोटद्वार रिखणीखाल में रिखणीखाल-सतपुली मोटर मार्ग पर कलवाड़ी गांव के पास हुआ। एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक समेत छह महिलाओं की मौत हो गई।



वाहन में सवार महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं और बैंक का काम निपटाकर अपने गांव लौट रही थीं। जानकारी के अनुसार, रिखणीखाल ब्लॉक के कोटनाली भंगलवाण की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैंक के काम को निपटाने सिद्धखाल गई थीं। काम पूरा करने के बाद सभी वाहन से अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान कलवाड़ी गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया और करीब 100 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरा। वाहन में सवार 7 लोगों की मौत हो गई।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारतीय संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बना सियासी महासंग्राम!

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक पुनर्गठन या 2029 के चुनाव का मास्टरस्ट्रोक? संविधान का अनुच्छेद 368,106वां और प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन,1971 व 2011 बनाम 2027 जनगणना और 543 से 850 लोकसभा सीटों का गणित!दक्षिण भारत की हिस्सेदारी पर सवाल?महिला आरक्षण का मुद्दा और विपक्ष की चुनौती! संसद के विशेष सत्र पर पूरी दुनियाँ की नज़र! - समग्र व्यापक महा-विश्लेषण!

भारत की संसद में ऐतिहासिक राजनीतिक महासंग्राम! संभावित 850 सीटों का प्रस्ताव? महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व की जंग और 2029 का चुनावी समीकरण! एनडीए को चाहिए अतिरिक्त समर्थन, विपक्ष के पास भी है सत्ता का गणित बदलने का हथियार!

क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा भारत का सत्ता-समीकरण? 543 से 850 सीटें? 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, परिसीमन का विवाद और एनडीए के 320 सांसदों की दो-तिहाई बहुमत की परीक्षा! विपक्ष की रणनीति से पलट सकता है पूरा खेल!

वैश्विक स्तरपर वर्तमान वैश्विक प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रांति,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ा आधारित नीति निर्धारण के दौर में दुनियाँ के लोकतांत्रिक देश अपनी संसदों में कानून बनाते समय नवीनतम जनसंख्या आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं को आधार बना रहे हैं। अमेरिका की सीनेट और प्रतिनिधि सभा से लेकर ब्रिटेन तथा यूरोप की संसदीय व्यवस्थाओं तक बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेने की परंपरा दिखाई देती है। इसी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद का आगामी विशेष सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक संवैधानिक और लोकतांत्रिक घटनाक्रम बन गया है।केंद्र सरकार ने लोकसभा को सोमवार 30 नवंबर 2026 और राज्यसभा को बुधवार 2 दिसंबर 2026 से पुनःबैठाने का निर्णय लिया है।दोनों सदनों की बैठकें क्रमशः 30 नवंबर और 1 दिसंबर तथा 2 और 3 दिसंबर तक चल सकती हैं।संसदीय कार्यमंत्री ने 26 नवंबर को आवश्यक सरकारी कामकाज का हवाला दिया था,जबकि 27 नवंबर को उन्होंने यह भी कहा कि इस सत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक और राष्ट्रीय महत्व के विषय सामने आ सकते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि हालांकि शुक्रवार दिनांक 27 नवंबर 2026 तक शाम 6 बजे तक सरकार ने विधायी कार्यसूची में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संबंधी प्रस्तावों को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में यही दोनों विषय हैं।

साथियों बात अगर हम पहला महत्वपूर्ण पहलू,विशेष सत्र या मानसून सत्र का विस्तार? को समझने की करें तो इस घटनाक्रम की एक संवैधानिक और संसदीय बारीकी समझना जरूरी है।संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था। इसलिए आगामी बैठकें उसी सत्र के दूसरे भाग के रूप में आयोजित होने की बात सामने आई है। इसीलिए इसे राजनीतिक और समाचार विमर्श में विशेष बैठक कहा जा रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे पूरी तरह अलग नया सत्र मानना सही नहीं होगा। सरकार ने सामान्य शीतकालीन सत्र की बजाय यह संक्षिप्त कार्यक्रम क्यों चुना,इसपर विपक्ष सवाल उठा रहाहै।वहीं सत्ता पक्ष आवश्यक सरकारी कामकाज को इसका कारण बता रहा है। सदन की अधिसूचित कार्यसूची और कार्यवाही का कार्यक्रम सटीकता से निर्णायक होगा।

साथियों बात अगर हम दूसरा पहलू,543 से 850 सीटों तक लोकसभा का विस्तार!को समझने की करें तो प्रस्तावित संविधान संशोधन का सबसे बड़ा आकर्षण लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 तक करने की संभावना है।वर्तमान लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं।प्रस्तावित व्यवस्था में सीटों का विस्तार करके राज्यों के प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन करने की चर्चा है।तर्क है कि 1952 में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ था,तब मतदाताओं की संख्या लगभग 17 करोड़ थी और लोकसभा में 489 सदस्य थे।आज मतदाताओं की संख्या लगभग 98 करोड़ पहुंच चुकी है,लेकिन निर्वाचित लोकसभा सीटें 543 ही हैं।ऐसे में बढ़ती आबादी और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व आवश्यकताओं को देखते हुए सीटें बढ़ाना समय की मांग बताया जा रहा है।हालांकि 850 सीटों का आंकड़ा प्रस्तावित अधिकतम सीमा है, कोई अंतिम स्वीकृत सीट आवंटन नहीं। प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह विधायी प्रावधानों और परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

साथियों बात अगर हम तीसरा पहलू,1971 की जनगणना बनाम 2027 की जनगणना का सवाल! को समझने की करें तो परिसीमन विधेयक के तहत राज्यों के बीच सीटों के अनुपात को 1971 की जनगणना पर स्थिर रखने(25 वर्षों के लिए और बढ़ाने) और राज्यों के भीतर सीटों के पुनर्गठन के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव है।इसनिर्णय और 1971 बनाम 2027 की जनगणना के पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं (अ)1971 की जनगणना को आधार बनाने के प्रमुख कारण,दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान (संघीय संतुलन)-मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तमिलनाडु,केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है।यदि नई जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें बांटी जातीं, तो उत्तर भारत के तेजी से बढ़ती आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ जातीं और दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता। 50 प्रतिशत समान वृद्धि का फॉर्मूला- इस असंतुलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सीटों में एकसमान 50प्रतिशत वृद्धि करने और 1971 की जनगणना के अनुपात को अगले 25 वर्षों (2051 तक) के लिए फ्रीज (स्थिर) रखने का फॉर्मूला तैयार किया है। इससे लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़कर 850 (815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से) करने का रास्ता साफ होगा और किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी।अप्रैल 2026 की विफलता से सबक-अप्रैल 2026 में जब सरकार ने बिना इस संवैधानिक गारंटी के परिसीमन विधेयक पेश किया था तब विपक्ष के विरोध के कारण यह लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (298 पक्ष में, 230 विरोध में) हासिल नहीं कर सका था।(ब)2027 की जनगणना का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना- 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) के तहत लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33ब आरक्षण देने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त रखी गई थी।समय की बाध्यता- आगामी जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय है। यदि इस जनगणना के पूरे होने और उसके आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाती,तो 2029 के आम चुनावों तक महिला आरक्षण लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता।2011 की जनगणना का उपयोग- समय बचाने और 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से, प्रस्तावित संशोधन के तहत 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना पहले से प्रकाशित 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

साथियों बात अगर हम चौथा पहलू,महिला आरक्षण और 2029 का राजनीतिक लक्ष्य! को समझने की करें तो, सितंबर 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन को संबंधित जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। सरकार की मंशा इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की बताई जा रही है। अप्रैल 2026 में इसी उद्देश्य से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 तथा संबंधित विधायी प्रस्ताव सामने आए थे। सरकार का तर्क था कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन और लोकसभा की सीटों के पुनर्गठन को एक साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है। महिलाओं को मौजूदा सीटों में भी सटीकता से आरक्षण दिया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम पांचवां पहलू,एनडीए के 320 सांसद और दो-तिहाई बहुमत का कठिन गणित! को समझने की करें तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मतों का समर्थन आवश्यक है।वर्तमान लोकसभा की निर्धारित सदस्य संख्या 543 है लेकिन तीन रिक्तियों के कारण प्रभावी सदस्य संख्या 540 है।यदि सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं तो विधेयक के समर्थन में 360 मत चाहिए।

उपलब्ध राजनीतिक गणना के अनुसार एनडीए के पास लगभग 320 सांसद हैं।इनमें भाजपा के 241,नेशनल के 20, तेलुगु देशम पार्टी के 16,शिवसेना के 13, जनता दल यूनाइटेड के 12,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 तथा अन्य सहयोगियों के सांसद शामिल हैं।इस प्रकार पूर्ण उपस्थिति की स्थिति में सरकार को 40 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता होगी।

संपादकीय

सेहत का रेड अलर्ट

भारत तेजी से मधुमेह, मोटापे और उच्च रक्तचाप के मरीजों की राजधानी बन रहा है। घर के स्वास्थ्यवर्धक खाने को तिलांजलि देकर चटपटा खाने का जुनून युवा पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ियों में भी नजर आ रहा है। दरअसल, चीनी व यूरोपीय शैली के खाद्य पदार्थों में तीखे नमक, चीनी तथा अधिक वसा के इस्तेमाल से चटपटे व्यंजन बनाने का जुनून आज भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रहा है। खासकर बच्चे व नयी पीढ़ी के युवा इसके दीवाने हैं। लोक कल्याण का दम भरने वाली सरकारों की जन-स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी के चलते जीवन शैली के तमाम रोग पनप रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश देने पड़े हैं। निस्संदेह, देश मे बढ़ते जन-स्वास्थ्य संकट के बीच कोर्ट की यह सार्थक पहल है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि जिन भी उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो, उन पर अलग से लाल रंग की चेतावनी लगायी जाए। ऐसा करके कोर्ट ने कंपनियों की सुविधा के बजाय उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' को प्राथमिकता दी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नियामक संस्था खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रही है। यही वजह है कि देश की शीर्ष अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। जन स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक मात्रा में चीनी, नमक व वसा का मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में होने के बावजूद एफएसएसएआई कई अलग-अलग प्रस्तावों के बीच उलझा रहा। इसमें स्टार 'रेटिंग सिस्टम' भी शामिल रहा है। जिसको लेकर विषय विशेषज्ञों की राय थी कि 'स्टार रेटिंग सिस्टम' से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिम के प्रति सचेत करने के बजाय, उनमें चयन को लेकर भ्रम बढ़ सकता है। सही मायने में ऐसे किसी निर्देश में स्पष्टता होनी बेहद जरूरी है। विडंबना है कि देश में अत्यधिक प्रोसेस्ड यानी अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत में भारी वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि देश आज तमाम गैर-संचारी रोगों की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। फलतः भारत में मधुमेह, हाइपरटेंशन और मोटापे से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ये रोग जीवनशैली की विसंगतियों से पैदा हुए हैं। विडंबना है कि सीधे खाने के लिये तैयार खाद्य पदार्थों, मीठे पेय पदार्थों और डिब्बाबंद स्नैक्स के लिये बेहद आक्रामक मार्केटिंग के जरिये बच्चों व युवाओं को लुभाया गया। फलतः जन-स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में लाल चेतावनी चिन्ह लगाने का निर्देश समय की सख्त जरूरत है। इससे कंपनियां छोटे अक्षरों की आड़ में पोषण संबंधी जोखिमों को छिपा नहीं सकतीं। लाल चेतावनी पर उपभोक्ताओं का सीधा ध्यान जाएगा। रोजमर्रा के खान-पान की चीजों को चुनते समय, लोगों को जटिल पोषण तालिकाओं को समझने के लिये किसी विशेष ज्ञान या अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहीं जन-स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योग जगत को मुनाफे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एफएसएसएआई को चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के लिये वैज्ञानिक आधार पर तार्किक सीमाएं तय करनी चाहिए। उसे उद्योग जगत की तरफ से आने वाले किसी भी दबाव का सामना करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

भारतीय खाद्य संस्कृति पर आघातों से सुप्रीम कोर्ट चिन्तित

(लेखक - ललित गर्ग)

भारत की पहचान केवल उसकी आध्यात्मिकता, विविधता और संस्कृति से नहीं, उसकी रसोई से भी होती है। हमारी रसोई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य, ऋतु के साथ संतुलन और भोजन के साथ संस्कार जुड़े रहे हैं। दादी-नानी के हाथों का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह परिवार की सेहत की पहली पाठशाला था। दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ, अंकुरित अनाज, मसालों का संतुलित उपयोग और घर का ताजा भोजन भारतीय जीवन-पद्धति की ताकत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी थाली धीरे-धीरे बदल गई है। स्वाद के नाम पर बाजार ने हमारी रसोई में प्रवेश किया और सुविधा के नाम पर पैकेट ने घर की कड़ाही को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बदलती खाद्य संस्कृति के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश एक महत्वपूर्ण चेतावनी की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक वाले उत्पादों पर अलग-अलग स्पष्ट चेतावनी चिह्न हों। न्यायालय ने 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को प्रमुखता से दिखाने तथा 'हाई शुगर', 'हाई फैट और 'हाई साल्ट' जैसे स्पष्ट संकेत देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है-उपभोक्ता को वह जानकारी सामने मिले, जिसे वह छोटे अक्षरों में खोजते-खोजते अक्सर छोड़ देता है।

यह फैसला केवल लेबल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें चमकदार पैकेट देखकर भोजन की गुणवत्ता तय कर ली जाती है। आज बाजार में किसी उत्पाद का विज्ञापन उसकी पौष्टिकता से अधिक आकर्षक पैकेजिंग, स्वाद और सुविधा बेचता है। बच्चे रंगीन पैकेट से आकर्षित होते हैं, युवा त्वरित भोजन को जीवनशैली समझने लगे हैं और व्यस्त परिवारों के लिए डिब्बाबंद भोजन समय बचाने का आसान विकल्प बन गया है। समस्या तब पैदा होती है जब सुविधा धीरे-धीरे आदत और आदत बीमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भोजन का अर्थ बदल रहा है। भोजन कभी जीवन को पोषण देने की प्रक्रिया था, अब वह तेजी से उपभोग की वस्तु बन रहा है। अधिक नमक, अधिक चीनी और अधिक वसा हमारे स्वाद की इंद्रियों को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन शरीर की जरूरतों को नहीं। स्वाद की जीभ छोटी अवधि की खुशी चाहती है, जबकि शरीर दीर्घकालिक संतुलन मांगता है। बाजार ने हमारी जीभ को जीतने की कोशिश की है, अब हमें अपने विवेक को जीतना होगा।

भारत जैसे देश में यह चुनौती और गंभीर है, क्योंकि यहां भोजन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। हमारी परंपरा में 'जैसा अन्न वैसा मन' की धारणा रही है। भोजन को आयु, ऋतु, प्रकृति और श्रम के अनुरूप लेने की परंपरा थी। भारतीय रसोई में अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें आज दुनिया 'सुपरफूड' कहकर खोज रही है। बाजरा, जौ, दालें, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और स्थानीय खाद्य परंपराएं हमारी अपनी विरासत हैं। विडंबना यह है कि जिन खाद्य पदार्थों की ओर दुनिया स्वास्थ्य के लिए लौट रही है, हम उन्हीं को छोड़कर अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल को केवल उपभोक्ता अधिकार का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय खाद्य संस्कृति के पुनर्जागरण के अवसर के रूप में देखना चाहिए।

सरकार की जिम्मेदारी भी यहां बहुत बड़ी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि उत्पाद खाने योग्य है, यह भी देखना होगा कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव की जानकारी आसानी से मिले। एफएसएसएआई को वैज्ञानिक, स्पष्ट और उपभोक्ता-केंद्रित नियम बनाने होंगे। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, उनका प्रभावी निरीक्षण और कठोर पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसी दिशा में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार या अदालत की नहीं हो सकती। उपभोक्ता को भी अपनी थाली का प्रहरी बनना होगा। जिस प्रकार हम घर खरीदते समय कीमत, स्थान और गुणवत्ता देखते हैं, उसी प्रकार भोजन खरीदते समय उसके घटकों को देखना भी हमारी आदत बननी चाहिए। किसी पैकेट पर बड़ा 'हेल्दी' लिखा होना उसे स्वतः स्वस्थ नहीं बना देता। विज्ञापन स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र नहीं है। असली प्रमाण उसके पोषण संबंधी विवरण और हमारी आवश्यकता के बीच संतुलन है।

बच्चों के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चे विज्ञापन और पैकेजिंग से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि स्कूल के आसपास और डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहेगा, तो स्वस्थ भोजन उनके लिए 'उबाऊ' और अस्वास्थ्यकर भोजन 'मजेदार' बन जाएगा। इसलिए स्कूलों को केवल पाठ्यपुस्तकों में स्वास्थ्य शिक्षा देने के बजाय कैंटीन और परिसर के आसपास उपलब्ध भोजन के माध्यम से भी स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों और उनके विज्ञापनों पर नियंत्रण की दिशा में भी जोर दिया है। हमें यहां एक और क्रांतिकारी विचार पर काम करना होगा-'फूड लिटरेसी' को जनशिक्षा का हिस्सा बनाना। जिस तरह बच्चों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है, उसी तरह उन्हें खाद्य साक्षरता भी सिखाई जानी चाहिए। बच्चे जानें कि शुगर क्या करती है, अधिक नमक क्यों नुकसान पहुंचाता है, संतृप्त वसा क्या है, पैकेट पर लिखे पोषण-लेबल को कैसे पढ़ना है और ताजा स्थानीय भोजन क्यों बेहतर विकल्प हो सकता है। एक जागरूक बच्चा केवल स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा, वह अपने परिवार की भोजन-आदत भी बदल सकता है। साथ ही भारतीय खाद्य संस्कृति को आधुनिक रूप देकर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। स्वस्थ भोजन का अर्थ यह नहीं कि स्वाद छोड़ दिया जाए।

भारत के पास स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत संतुलन बनाने की हजारों वर्ष पुरानी क्षमता है। जरूरत है कि बाजरा, दाल, सब्जियों, पारंपरिक पेयों और स्थानीय व्यंजनों को आधुनिक प्रस्तुति, स्वच्छ पैकेजिंग और उचित मूल्य के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। हमें विदेशी खाद्य संस्कृति का विरोध नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को इतना आकर्षक बनाना है कि भारतीय युवा उसे गर्व से अपनाए।



प्रजा का खजाना

फारस के शासक साइरस अपनी प्रजा की भलाई में जुटे रहते थे। लेकिन खुद उनका जीवन सादगी से भरा था। वह रियासत की सारी आमदनी व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी में लगा देते थे। इस कारण शाही खजाना हल्का रहता था। लेकिन प्रजा खुशहाल थी। एक दिन साइरस के दोस्त और पड़ोसी शासक प्रोशियस उनके यहां आए। उनका मिजाज साइरस से बिल्कुल अलग था। उन्हें प्रजा से ज्यादा अपनी खुशहाली की चिंता रहती थी। उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। बातों-बातों में जब प्रोशियस को साइरस के खजाने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने साइरस से कहा, अगर आप इसी तरह प्रजा के लिए खजाना लुटाते रहोगे तो एक दिन वह एकदम खाली हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे। अगर आप भी मेरी तरह खजाना भरने लगें तो आपकी गिनती मेरी तरह सबसे धनी शासकों में होने लगेगी।

साइरस मुस्कराए फिर बोले आप दो दिन ठहरिए मैं इस मामले में लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। उन्होंने घोषणा करवा दी कि एक बहुत बड़े काम के लिए साइरस को दौलत की निहायत जरूरत है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रजा मदद करेगी। दो दिन पूरा होने से पहले ही शाही महल के बाहर मोहरों, सिक्कों व जेवरों का बड़ा ढेर लग गया। यह



देख प्रोशियस हैरत में पड़ गए। साइरस ने कहा, मैंने रियासत का खजाना लोगों की खुशहाली पर खर्च करके एक तरह से उन्हीं को सौंप दिया है। लोग उसमें इजाफा करते रहते हैं। मुझे जब जरूरत होगी वे मुझे लौटा देंगे जबकि तुम्हारा खजाना बांझ है, वह कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है।

विचार मंथन

सोना सस्ता होने से गोल्ड लोन लेने वालों पर मुसीबत का पहाड

(लेखक - सनत जैन)

पिछले 27 दिन में सोने की कीमतों में करीब 13.58 फीसदी की गिरावट आई है। गिरवी रखे सोने और गहनों पर अतिरिक्त रकम जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। भुगतान नहीं करने पर नीलामी का खतरा बढ़ गया है। भारत में सोना केवल आभूषण या निवेश का माध्यम नहीं है, करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। जब परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आता है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी होती है, इलाज कराना होता है, या पुराने कर्ज की किस्त चुकानी होती है, तब घर में रखा सोना काम आता है। लोग अपनी जरूरत के लिए सोने को गिरवी रखकर जरूरत पूरी करते हैं। अब यही आर्थिक सहारा कई परिवारों के लिए नई परेशानी का कारण बनता जा रहा है। पिछले 26 दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 13.58 फीसदी की गिरावट, दूसरी तरफ गोल्ड लोन बढ़कर 8.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का आंकड़ा वित्तीय व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सोने की कीमत घटने से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए गिरवी रखे सोने का मूल्य कम हुआ है। ऐसे में कर्ज देने वाली संस्थाएं ग्राहकों से अतिरिक्त सोना या बकाया राशि जमा करने की मांग कर रही हैं। जिन परिवारों ने अपनी सोने के रूप में रखी पूरी बचत गिरवी रखकर कर्ज लिया है, उनके लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो गई है। इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है, गोल्ड लोन का विस्तार केवल निवेश या कारोबार की जरूरतों मे नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में परिवार अपनी रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। कई लोग पुराने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नया गोल्ड लोन ले रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों का खर्च, बच्चों की शिक्षा, घरेलू जरूरतें और शादी-विवाह जैसे सामाजिक दायित्व भी इसकी बड़ी वजह हैं। इसका अर्थ यह है, भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर वर्तमान जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

सीआरआईएफ की नवंबर 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक देश में गोल्ड लोन का बकाया पोर्टफोलियो 23.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 60.6 फीसदी अधिक है। सक्रिय गोल्ड लोन खातों की संख्या 10.2 करोड़ हो गई है। जुलाई-सितंबर तिमाही में नए गोल्ड लोन का मूल्य 8.15 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 27.2 फीसदी की वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि इस दौरान लोन खातों की संख्या 4.1 फीसदी घटी है। इसके बावजूद भी औसत लोन की राशि 32.7 फीसदी बढ़कर 2.2 लाख रुपये हो गई। यानी कम खातों के बावजूद लोग पहले की तुलना में बड़ी रकम उधार ले रहे हैं। गोल्ड लोन का विस्तार अब बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा। सीआरआईएफ के आंकड़ों के अनुसार, छोटे शहरों और कस्बों में भी गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं के गोल्ड लोन खातों की संख्या बढ़कर 2.4 करोड़ पहुंच गई है। कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में महिलाओं की हिस्सेदारी 42.2 फीसदी पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा बताता है, परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महिलाओं के गहने भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं।

दक्षिण भारत के पांच राज्यों की हिस्सेदारी कुल बकाया गोल्ड लोन में लगभग 72 फीसदी है। दूसरे राज्यों में भी गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोने की कीमतों में गिरावट का सीधा असर गिरवी रखे सोने के बदले दिए गए कर्ज पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने सोने की ऊंची कीमत के समय 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था. अब गिरावट के कारण गिरवी रखे सोने का मूल्य कम हो गया है। इससे कर्जदाता के लिए जोखिम बढ़ जाता है। लोन और गिरवी रखे सोने के वर्तमान मूल्य के बीच का अनुपात बढ़ने से ग्राहक को अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त सोना जमा करने के नोटिस शुरू हो गए हैं। हर बैंक या एनबीएफसी तत्काल अतिरिक्त भुगतान की मांग नहीं कर सकती है। यह लोन की शर्तों, निर्धारित लोन-टू-वैल्यू अनुपात और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। भुगतान नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के पश्चात गिरवी रखे सोने की नीलामी हो सकती है। हालिया बाजार रिपोर्टों में गोल्ड लोन कंपनियों पर बढ़ते दबाव और नीलामी के अंदेशे का में उल्लेख किया गया है। गोल्ड लोन में लगातार बढ़ोतरी के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है, जिन परिवारों की बचत धीरे-धीरे कर्ज के बोझ में बदल रही है। यदि सोने की कीमतें भविष्य में और भी गिरती हैं, जिन्होंने लोन लिया है उनकी आमदनी में सुधार नहीं होता है, तो कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित होगी। इससे बैंकों और और लोन देने वाली कंपनियों के सामने वसूली तथा खराब कर्ज का जोखिम बढ़ सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक के लिए भी यह समझना जरूरी है, गोल्ड लोन का विस्तार आर्थिक गतिविधियों में बदलाव का संकेत है, या घरेलू आर्थिक मजबूरी का परिणाम है। केवल कर्ज वितरण बढ़ने को वित्तीय सफलता नहीं माना जा सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक को यह भी देखना होगा, लोग कर्ज लेकर रोजगार, कारोबार और आय बढ़ा रहे हैं, या पुराने कर्ज और घरेलू खर्च को पूरा करने लोन ले रहे हैं। अंततः सोने की कीमतों में गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों को हो रहा है, जिनके पास संकट के समय गिरवी रखने के लिए यही एक संपत्ति थी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

स्वराज ग्रीन पावर ने आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए

नई दिल्ली ।

एकीकृत एथनॉल उत्पादक और चीनी विनिर्माता स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड ने बाजार नियामक सेबी के पास अपने 1,100 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए अद्यतन मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं।

इस प्रस्तावित आईपीओ में 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक रंजीतसिंह हिंदूराव नाइक निंबालकर 300 करोड़ रुपये के शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत बेचेंगे। नए निर्गम से प्राप्त 620.85 करोड़ रुपये का उपयोग मौजूदा कर्जों के भुगतान के लिए होगा, शेष सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों में लगेगी।

कंपनी आईपीओ से पहले 160 करोड़ रुपये तक के निजी नियोजन पर भी विचार कर सकती है, जिससे नए शेयरों का आकार घट जाएगा।

महाराष्ट्र के सतारा में स्थित यह कंपनी एथनॉल उत्पादन और चीनी विनिर्माण का एकीकृत कारोबार करती है।

अदाणी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 2.2 लाख करोड़ का निवेश किया

निवेश में 41 फीसदी की वृद्धि, घरेलू बाजारों से जुटाई जाएगी 70-75 फीसदी पूंजी

मुंबई ।

विविध कारोबारों में सक्रिय अदाणी समूह चालू वित्त वर्ष (2024-25) में अपने पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि करने जा रहा है। समूह ने इस अवधि में 2.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत से अधिक है। समूह के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अदाणी समूह के पास सालाना 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश करने की वित्तीय क्षमता है, लेकिन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की क्रियान्वयन क्षमता फिलहाल सीमित है।

समूह अपनी कुल पूंजी जरूरतों का 70-75 प्रतिशत घरेलू पूंजी बाजार से जुटाने की योजना बना रहा है, फिलहाल 56 फीसदी हिस्सा यहीं से आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने के लिए समूह वित्त वर्ष 2027-28 में डॉलर में सार्वजनिक बॉन्ड जारी करने पर विचार कर सकता है। समूह का कुल सकल कर्ज लगभग 3.2-3.3 लाख करोड़ रुपये है और शुद्ध कर्ज तथा कर-पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) का अनुपात 2.8-3 गुना है। उन्होंने कहा कि भारत के व्यापार समझौतों से समूह के हवाईअड्डा और बंदरगाह कारोबार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

नेस्ले इंडिया पर ईपीएफओ की कार्रवाई, 36 लाख जमा करने का आदेश

2012-2019 के बीच भविष्य निधि संबंधी विसंगतियों पर लगाया गया जुर्माना

नई दिल्ली ।

मैगी, किटकैट और नेसकैफे जैसे लोकप्रिय उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से बड़ा झटका लगा है।

ईपीएफओ ने कंपनी को 2012 से 2019 के बीच भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़ी विसंगतियों के लिए 36.36 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है।

ईपीएफओ के मैसूर कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश में कंपनी पर लगभग 20.09 लाख रुपए का हर्जाना और पेनल्टी भी शामिल है। यह आदेश कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7क्यू और धारा 14क्यू के तहत जारी किया गया है। धारा 7 क्यू पीएफ भुगतान में देरी पर ब्याज का प्रावधान करती है, जबकि धारा 14बी चूक या देरी पर पेनल्टी लगाने का अधिकार देती है।

नेस्ले इंडिया ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि इस आदेश का उसके कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।

हालांकि, इस घटना ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़े नियमों के सही और समय पर अनुपालन के महत्व को एक बार फिर उजागर किया है। कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी या मांगी गई राशि जमा करेगी। ईपीएफओ का यह कदम पीएफ नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उठापटक भरा रहा बीता सप्ताह, निवेशकों की धड़कनें तेज

आईटी और एचडीएफसी बैंक में भारी बिकवाली, कच्चे तेल ने भी बढ़ाई चिंता

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसने निवेशकों को लगातार सस्पेंस में रखा। बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने एक ही सप्ताह में भारी गिरावट, मजबूत वापसी और फिर मुनाफावसूली के कारण महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया। यह सप्ताह बाजार की अंतर्निहित अस्थिरता को दर्शाता है, जहां शुरुआती झटके को आक्रामक खरीद से भरपाई किया गया, लेकिन अंततः बिकवाली का दबाव हावी रहा। सप्ताह की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए झटकेदार रही। सोमवार को शुरुआती मजबूत बढ़त कुछ ही मिनटों में काफूर हो गई और बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में आ गए। दिन के उच्च स्तर से सेंसेक्स में 1,700 अंक से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, और यह 1.76 फीसदी की हानि के साथ 82,435.99 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1.75 फीसदी गिरकर 25,349.65 पर समाप्त हुआ। धातु, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में हुई तेज बिकवाली इस गिरावट का मुख्य



कारण रही। मंगलवार को गुरुनानक जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहे, जिसने निवेशकों को सोमवार की गिरावट से उबरने का एक दिन दिया। बुधवार को बाजार ने जोरदार वापसी की, और यह निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत थी। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1,502 अंक से अधिक उछलकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने 25,800 का अहम स्तर पार कर लिया।

व्हाइट लेबल एटीएम को आरबीआई से सीधे कैश मिलेगा

कंपनियां अब एक बैंक पर निर्भर नहीं रहेंगी

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) कंपनियों के लिए कैश आपूर्ति संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन नए निर्देशों से अब इन एटीएम ऑपरेटरों को नकदी भरने के लिए सिर्फ एक बैंक पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। नए नियमों के अनुसार व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (निजी कंपनियां द्वारा संचालित एटीएम) अब सीधे आरबीआई के इश्यू ऑफिस और करेंसी चेस्ट से थोक में नकदी खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम एक लाख नोटों का पूरा भुगतान करना होगा और अपने एटीएम की लोकेशन की सूची प्रदान करनी होगी। पहले, ये कंपनियां केवल अपने प्रायोजक बैंक पर निर्भर करती थीं।

आरबीआई ने डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी नकदी लेने की अनुमति दी है। वे अब एक से अधिक प्रायोजक बैंकों के साथ समझौता कर सकेंगे, जिससे नकदी की आपूर्ति में लचीलापन आएगा। नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एटीएम में डाले गए नोटों के असली होने की जिम्मेदारी कैश सप्लाई करने वाले बैंक की होगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी की उपलब्धता को बढ़ाना और उनकी परिचालन दक्षता में सुधार कर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है।

टेलीकॉम कंपनियों को इंटर-कनेक्शन दरें सार्वजनिक करना अनिवार्य-ट्राई

30 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनियों पर लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली ।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और सभी सेवा प्रदाताओं के लिए नेटवर्क तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जारी संशोधित नियमों के तहत अब 30 प्रतिशत या उससे अधिक बाजार हिस्सेदारी रखने वाली दूरसंचार कंपनियों को अपनी इंटर-कनेक्शन दरों को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। ये नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जिन्हें महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) वाला माना जाएगा।

एसएमपी का निर्धारण समायोजित सकल राजस्व, ग्राहकों की संख्या, वॉयस कॉल क्षमता और ट्रैफिक की मात्रा जैसे चार मानकों के आधार पर 30 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी होने पर किया जाएगा। ऐसे सेवा प्रदाताओं को एसएमपी घोषित होने के 30 दिनों के भीतर नियामक को अपना संदर्भ इंटर-कनेक्शन प्रस्ताव (आरआईओ) जमा करना होगा और मंजूरी के 15 दिनों के भीतर इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ट्राई का यह कदम रिलायंस जियो के 2015 में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों द्वारा नेटवर्क पहुंच न दिए जाने की शिकायत जैसी अतीत की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा।

आरबीआई गवर्नर ने निर्यातकों को चेताया, एफटीए का पूरा लाभ नहीं उठा रहे एमएसएमई

भारत के केवल 20-30 फीसदी पात्र निर्यात ही टैरिफ रियायतों का लाभ उठा रहे, जबकि साझेदार देश 60-70 फीसदी

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को चेतावनी दी कि वे देश के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से मिलने वाले लाभों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने घरेलू बाजारों से परे जाकर वैश्विक अवसरों को भुनाने और उत्पादों की गुणवत्ता में निवेश करने का आग्रह किया। मुंबई में एसएमई फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि जहां भारत के केवल 20-30 प्रतिशत पात्र निर्यात ही एफटीए के तहत टैरिफ रियायतों का लाभ उठा रहे हैं, वहीं भारत को निर्यात करने वाले साझेदार देश इन समझौतों का उपयोग 60-70 प्रतिशत तक कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा छूटा हुआ अवसर बताया। आरबीआई गवर्नर ने एमएसएमई क्षेत्र से एफटीए प्रावधानों की बेहतर जानकारी हासिल करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए गुणवत्ता, मानकों तथा प्रमाणन में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता एफटीए नेटवर्क एमएसएमई के लिए नए बाजारों तक पहुंच और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, मल्होत्रा ने एमएसएमई क्षेत्र को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण में महत्वपूर्ण सुधार का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 को समाप्त 12 महीनों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 27 प्रतिशत बढ़ा, जो बैंकिंग प्रणाली के कुल ऋण वृद्धि दर 19.4 प्रतिशत से काफी अधिक है। एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया ऋण सितंबर 2021 के 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2026 में 42.89 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 19 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है। आरबीआई गवर्नर ने स्वीकार किया कि ऋण अंतर (क्रेडिट गैप) कम हुआ है, लेकिन अब पहली बार ऋण लेने वाले उद्यमियों, सूक्ष्म इकाइयों, महिला-संचालित व्यवसायों तथा छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए वित्तपोषण को आसान बनाने हेतु उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। मल्होत्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से, आरबीआई ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आवश्यक कोलैटरल-फ्री लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, जो 2010 के बाद पहला बदलाव है। बैंक मजबूत प्रदर्शन वाले उधारकर्ताओं के लिए इस सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं।

बिसलेरी ने एफएसएसएआई के दावों को नकारा,स्वतंत्र जांच में पानी खरा

नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी

नई दिल्ली ।

बोतलबंद पेयजल विनिर्माता बिसलेरी ने एफएसएसएआई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लिए गए उसके पानी के नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। कंपनी ने शनिवार को कहा कि दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की जांच में उसका पानी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है, और उसने एफएसएसएआई से नतीजों में अंतर की जांच करने का आग्रह किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जलपाईगुड़ी की एक विनिर्माण इकाई से लिए गए नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी के बाद बिसलेरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दी थी। यह नमूना 12 अगस्त, 2026 को प्रतिबंधित एक विशिष्ट बैच (पीबी201) का था। एफएसएसएआई के निर्देश पर बिसलेरी ने तुरंत इस बैच को बाजार से वापस मंगा लिया था। हालांकि, कंपनी ने उसी बैच के नमूनों की एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त दो अलग-अलग स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच कराई। इन दोनों स्वतंत्र जांचों में पाया गया कि नमूना कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सहित सभी लागू खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा। बिसलेरी ने नियामक और अपनी स्वतंत्र जांच के निष्कर्षों में इस बड़े अंतर पर चिंता व्यक्त की है। कंपनी ने एफएसएसएआई से नमूना लेने की प्रक्रिया, परीक्षण पद्धति और प्रयोगशाला परिणामों में अंतर के लिए जिम्मेदार कारकों की गहन समीक्षा करने का आग्रह किया है।

बिसलेरी ने कहा है कि वह तथ्यों को स्थापित करने के लिए एफएसएसएआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और उम्मीद है कि मामले का आकलन उद्योग पर लागू समान मानकों पर होगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में अग्रसर- वाणिज्य सचिव

छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल

जयपुर ।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता लगातार जारी है। उन्होंने एक ऐसे लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की दिशा में काम करने पर जोर दिया, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। साथ ही, सरकार छोटे व्यवसायों को निर्यात के अवसरों से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां भारत का 90 अरब डॉलर से अधिक का वस्तु निर्यात होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश निरंतर बातचीत के माध्यम से एक ऐसे एफटीए को अंतिम रूप देना चाहते हैं, जिससे आपसी व्यापार को बढ़ावा मिले।

हालांकि, उन्होंने समझौते के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताने में असमर्थता व्यक्त की, पर इस साल निर्यात बढ़ने और मजबूत व्यापारिक संबंधों पर संतोष जताया। सरकार छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को निर्यात के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए सक्रिय है।

आरबीआई दिसंबर में बढ़ा सकता है रेपो रेट

होम लोन, कार लोन होंगे महंगे, महंगाई और मजबूत आर्थिक वृद्धि दर बन रहे वजह

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 4 दिसंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों पर बड़ा फैसला आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक इस बार रेपो रेट में 0.25 फीसदी के बजाय सीधे 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे यह बढ़कर 6 फीसदी तक पहुंच जाएगा। नोमुरा के अनुसार नवंबर में खाद्य वस्तुओं, खासकर अनाज और दालों की कीमतों में तेजी आई है, जिससे खुदरा महंगाई दर 6.4 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। यह आरबीआई के 6 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है। इसके अलावा, मजबूत आर्थिक वृद्धि दर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक कारण बन सकती है। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5 फीसदी से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो केंद्रीय बैंक के अनुमान से अधिक है।

इस संभावित बढ़ोतरी से होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज महंगे हो जाएंगे, साथ ही मौजूदा ईएमआई भी बढ़ सकती है। नोमुरा ने 0.50 फीसदी बढ़ोतरी की 60 फीसदी और 0.25 फीसदी बढ़ोतरी की 40 फीसदी संभावना जताई है। दिसंबर की इस बढ़ोतरी के बाद कुछ समय दरों में स्थिरता दिख सकती है, पर फरवरी या अप्रैल में 0.25 फीसदी की और वृद्धि की संभावना बनी रहेगी, जो महंगाई और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। यह फैसला बॉन्ड बाजार और आम लोगों के लिए काफी अहम होगा।

अडानी ग्रुप की एविएशन में नई उड़ान, निवेश की तैयारी

सरकार से मांगी अनुमति, बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को भुनाने की रणनीति

नई दिल्ली ।

भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप अब एयरलाइन कारोबार में निवेश की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समूह ने सरकार से आधिकारिक अनुमति मांगी है, ताकि वह हवाई यात्रा की बढ़ती मांग का फायदा उठा सके। यह कदम देश के एविएशन मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अडानी ग्रुप, जो पहले से ही देश के आठ प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करता है, अब एयरलाइन कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रहा है। समूह ने इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। यदि यह मंजूरी मिल जाती है, तो अडानी ग्रुप किसी मौजूदा एयरलाइन में शेयर खरीद सकेगा या निवेश फंड के माध्यम से इस सेक्टर में पूंजी लगा सकेगा। अडानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने इस रणनीति की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में हवाई यात्रा की मांग में असाधारण वृद्धि देखने को मिल रही है। उनके मुताबिक भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनमें हवाई यात्रा करने की क्षमता है और भविष्य में देश को प्रतिदिन लगभग 30,000 फ्लाइट्स की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान क्षमता से लगभग 10 गुना अधिक है। इतनी विशाल मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा एयरलाइंस और बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी, और अडानी ग्रुप इसी विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि, समूह ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब अपनी खुद की नई एयरलाइन शुरू करना नहीं है। वर्तमान में, अडानी ग्रुप मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स का संचालन कर देश के कुल हवाई यात्रियों के एक चौथाई से अधिक हिस्से को संभालता है।

एयरपोर्ट के कारोबार में गहरी पकड़ होने के बाद अब एयरलाइन सेक्टर में निवेश की अनुमति मिलने पर समूह की पहुंच एविएशन के एक और महत्वपूर्ण हिस्से तक बढ़ जाएगी, जिससे उसकी एविएशन वैल्यू चेन और मजबूत होगी।

यूरोप की सबसे बड़ी टेक कंपनी एसएपी में 10,000 नौकरियों पर खतरा

जर्मन सॉफ्टवेयर दिग्गज एआई-फर्स्ट बिजनेस बनने को तैयार

नई दिल्ली ।

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बढ़ता दखल अब रोजगार बाजार पर सीधा असर डाल रहा है। इसी कड़ी में जर्मनी की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी अपने बिजनेस को एआई के हिसाब से ढालने की तैयारी में है, जिसके चलते उसके 10,000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। यह कंपनी के वैश्विक कार्यबल का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है, और यह कदम एआई को अपने कोर ऑपरेशंस में गहराई से एकीकृत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एसएपी अपने आप को एक एआई-फर्स्ट बिजनेस में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग बढ़ाएगी, और इसके लिए उत्पादों को बनाने तथा बेचने के तरीकों में भी मूलभूत बदलाव किए जाएंगे। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में, सभी विभागों से उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है जहां कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष रूप से उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और बिक्री (सेल्स) विभागों पर पैनी नजर है।

हालांकि, एसएपी ने अभी तक 10,000 पदों को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह घोषणा आमतौर पर कंपनी के सालाना वित्तीय नतीजों के साथ जनवरी के आखिर में की जा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब एसएपी इतने बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में है; साल 2024 में भी कंपनी ने लगभग 10,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला था, जिस पर 3 अरब यूरो (लगभग 3.3 अरब डॉलर) का खर्च आया था और इसे पूरा होने में एक साल से ज्यादा लगा था।

एटीएम से पैसे निकालने से पहले जानें अपने चार्ज!

अब बैंक बताएंगे कितने फ्री ट्रांजैक्शन बचे, अनचाहे शुल्क से बचाने की पहल

नई दिल्ली ।

यदि आप अक्सर एटीएम से नकदी निकालते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए नियम आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। नये नियमों के अनुसार बैंक अब ग्राहकों को उनके मासिक मुफ्त एटीएम लेनदेन की संख्या और सीमा पार होने पर लगने वाले संभावित शुल्क की जानकारी पहले से देंगे। यह कदम लेनदेन में अधिक पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को अप्रत्याशित शुल्कों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एटीएम और पीओएस से नकदी निकासी से संबंधित 2008 से 2022 के बीच जारी 17 पुराने सर्कुलर को समेटते हुए एक नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। इसके तहत बैंकों को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी होगी जो ग्राहकों को उनके फ्री ट्रांजैक्शन की स्थिति और अगली निकासी पर संभावित शुल्क के बारे में सूचित करे। इससे उपभोक्ता अपनी नकदी निकासी को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले सकेंगे। मुफ्त लेनदेन की सीमा की बात करें तो आप अपने बैंक के



एटीएम से महीने में 5 बार तक मुफ्त निकासी कर सकते हैं। वहीं, अन्य बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 बार तक मुफ्त लेनदेन की सुविधा मिलती है। सीमा पार होने पर, बैंक अधिकतम 23 रुपये प्रति लेनदेन (प्लस लागू कर) का शुल्क लगा सकते हैं। हालांकि, तकनीकी खराबी या एटीएम में नकदी न होने के कारण असफल हुए लेनदेन को मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में नहीं गिना जाएगा और इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



वॉटर पार्क ...हो जाए मस्ती

गर्मी में पानी के अंदर खेलने व मस्ती करने में खूब मजा आता है। बात अगर वॉटर पार्क की हो तो ये मजा दोगुना समझो। पार्क की राइड्स, झूले तो तेज धूप के असर को मानो छूमंतर कर देते हैं।

गर्मी में पानी से खेलकर सबसे ज्यादा राहत मिलती है। इसीलिए इस मौसम में वॉटर पार्क में काफी संख्या में लोग जाते हैं। वहां की स्लाइड, स्विमिंग पूल, रेन डांस के बीच एक पूरा दिन बिताना सबको भाता है। पानी में खूब भीगना, फिर पसंदीदा खाना और खूब सारे झूले किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं होते।



दिल्ली राइड्स

दिल्ली के कालिंदी कुंज का दिल्ली राइड्स वॉटर पार्क के साथ एम्यूजमेंट पार्क भी है। वॉटर पार्क में मौजूद हर राइड में पानी की बौछारें मिलेंगी। यहां





हां सभी तरह की पार्टी आयोजित की जा सकती हैं, जैसे बर्थडे ार्टी, किटी पार्टी। यहां पिकनिक भी मना सकते हो।

ज़स्ट चिल

स्ट चिल भी जीटी करनाल रोड पर है। यहां पर रेनबो, ब्लैक थ्रिल, मनी एक्वा राइड्स, फ्रेंडशिप, गॉडजिला जैसी वॉटर राइड्स कर कते हो। इसके अलावा तुम यहां एडवेंचर गेम्स भी खेल सकते हो। डोर-आउटडोर गेम्स यहां खेलने की सुविधा है।

फन एंड फूड विलेज

फन एंड फूड विलेज दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर से लगा है। यहां पूरे रिवार के साथ रेन डांस कर सकते हो। यहां सबसे लंबा वॉटर ानल 'लेजी रिवर' है।

ग्राइम लांग है सबसे बड़ा पार्क

ुनिया का सबसे बड़ा वॉटर पार्क चीन में । इसका नाम चाइम लांग ओशन किंगडम है। 200 अरब रुपए की लागत से बने इस वॉटर पार्क में 7 थीम एरियाज हैं। इनमें बड़े एक्वेरियम, खूब सारी राइड्स, 5डी सिनेमा और सर्कस हैं। चारों तरफ पानी, मछलियां और समुद्री जीव और बीच में कांच की सुरंग से लोग गुजरते हैं। यहां व्हेल समेत कई दुर्लभ प्रजाति की मछलियां भी रखी गई हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इसके अलावा चाइम लांग में 1278 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचाई वाला रोलर कोस्टर भी है।

ये ले जाना साथ...

सबसे पहले एक छोटा सा बैग लो, जिसमें कुछ कपड़े रख सको। दो तौलिया रखो। वॉटर पार्क में खाने का सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए लंच तो वहीं करना होगा। सनस्क्रीन रखना मत भूलना। एक जोड़ी कपड़े रख लो। लौटते वक्त भीगे हुए स्विमिंग सूट रखने के लिए एक प्लास्टिक बैग भी रख लेना। कुछ डिस्पोजेबल पानी की बोतलें भी रख सकते हो। सनग्लासेज भी जरूरी हैं। बाथिंग जेल या साबुन, एक हैट, और एक जोड़ी स्लिपर्स रखना न भूलना।

वर्ल्डस ऑफ वंडर

नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल के पास वर्ल्डस ऑफ वंडर वॉटर पार्क है। इसमें 26 तरह की वॉटर राइड का मजा तुम उठा सकते हो। साथ ही एम्यूजमेंट पार्क भी है। यहां गो कार्टिंग भी होती है।

कितना आएगा खर्च

कई जगह छोटे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है, तो कहीं पर बर्थडे वाले दिन फ्री में एंट्री मिलने के ऑफर दिए जा रहे हैं। दिल्ली राइड्स में टिकट की कीमत 250 से 600 रुपए के बीच है, वहीं स्प्लैश वॉटर पार्क में कई तरह के कार्ड बनवाकर साल भर की मेंबरशिप भी ली जा सकती है। बच्चों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 345 रुपए और शनिवार, रविवार व पब्लिक होलीडे में 460 रुपए टिकट रखी गई है। जस्ट चिल वॉटर पार्क में सोमवार से शुक्रवार तक 300 रुपए और शनिवार, रविवार व हॉलीडे में 400 रुपए का टिकट है। फन एंड फूड विलेज में बच्चे की टिकट 600 रुपए है। ज्यादातर वॉटर पार्क्स सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं।

क्लब प्लेटिनम रिसॉर्ट

क्लब प्लेटिनम दिल्ली-रोहतक रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा में है। इसे फनटाउन भी कहा जाता है। यहां वॉटर पार्क और रिसॉर्ट है। इसमें अच्छे वॉटर स्लाइड्स, स्विमिंग पूल और छोटा एम्यूजमेंट पार्क है। वॉटर पार्क में मैजिक ट्विस्ट ब्लैक टनल, मल्टी लेन स्लाइड, फैमिली स्लाइड्स, स्पारइरल स्लाइड और डांस फ्लोर भी है।

वेट एंड वाइल्ड

धौला कुआं से 30 किमी दूर इस रिसॉर्ट में वॉटर पार्क की सारी राइड्स हैं। स्विमिंग पूल का मजा भी ले सकते हैं। यहां आप न केवल पार्टी कर सकते हैं, बल्कि आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं।

स्प्लैश वॉटर पार्क

यह जीटी करनाल रोड पर है। इस पार्क में बुद्धा वॉटर फॉल, मशरूम फॉल, मल्टीलेन स्लाइड्स हैं।





मोहल्ले में चार-पांच कुत्ते एक साथ रहते थे। उन्हीं में पिन्टू नाम का एक डॉगी था। उसे झम्मुक लाल की डांट-फटकार अच्छी नहीं लगती थी। उसके साथी भी झम्मुक लाल से परेशान रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा।

वफादार पिन्टू

झम्मुक लाल को कुत्तों से बड़ी नफरत थी। उनकी कर्कश आवाज सुनते ही वह तिलमिला जाते थे। रात में जब भी उनके भौंकने की आवाज सुनते, तुरंत अपना बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ते। कुत्तों को भी उनको दौड़ाने में खूब मजा आता था। कुत्तों में आदत होती है कि जब भी उन्हें किसी दूसरे मोहल्ले का कोई कुत्ता या कोई ऐसा व्यक्ति, जो अजीब तरह के कपड़े पहने हो, दिखाई देता है तो वे उस पर तुरंत भौंकना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वह उनके इलाके से बाहर न निकल जाए। झम्मुक लाल कुत्तों से तब और परेशान हो जाते थे, जब उनके घर के आसपास वे गंदगी कर देते थे, इसलिए जहां भी कुत्ते दिखते, वो उन्हें वहां से भगा देते। कुत्ते उन्हें अच्छी तरह से पहचान गए थे। उनकी गली में चार-पांच कुत्ते एकसाथ रहते थे। उन्हीं में पिन्टू नाम का एक डॉगी था। उसे झम्मुक लाल की डांट-फटकार अच्छी नहीं लगती थी। उसके साथी भी झम्मुक लाल से परेशान रहने लगे थे। उन्होंने एक दिन आपस में मीटिंग की और कहा कि झम्मुक लाल हमें कहीं पर भी खड़ा नहीं होने देता। हम कहीं पर भी भौंकते हैं तो वह हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगता है। हम उससे कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर भी वह हमारे पीछे दौड़कर हमें कई बार चोट भी पहुंचा चुका है। इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। उन कुत्तों में पिन्टू कुछ शरारती किस्म का छोटा सा डॉगी था। उन कुत्तों ने झम्मुक लाल को मजा चखाने के लिए पिन्टू डॉगी को ही जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि पीछे से हम तुम्हारा साथ देंगे।

झम्मुक लाल ढीला-ढाला कुर्ता-पायजामा पहना करते थे और अपने मोहल्ले के भी प्रधान थे। एक दिन कुत्तों ने एक योजना बनाकर उनके घर के सामने भौंकना शुरू कर दिया। उनके घर से बाहर डंडा लेकर निकलने से पहले ही सभी कुत्ते छिप गए। झम्मुक लाल जैसे ही डंडा लेकर बाहर निकले, पीछे से अचानक पिन्टू ने उनका ढीला कुर्ता मुंह से पकड़ लिया और पीछे से उसके दूसरे साथियों ने भौंकना शुरू कर दिया। अब तो काटने के डर से डंडा वहीं पर छोड़ झम्मुक लाल उल्टा घर की ओर भाग लिए। झम्मुक लाल की सासें तेज-तेज चलने लगी थीं। वे सोचने लगे, पहले तो मैं ही इन्हें डंडे से डराया करता था, अब उल्टा ये मुझे डराने लगे हैं। झम्मुक लाल जब भी घर से बाहर निकलते पिन्टू तुरंत चुपके पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लेता और झम्मुक डर की वजह से उल्टे घर की ओर भागने लगते। अब उन्हें पिन्टू से डर लगने लगा था। उन्होंने अपनी गली की एक दिन मीटिंग बुलाई और और उस पिन्टू डॉगी को वहां से कहीं बाहर भिजवा दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि पिन्टू डॉगी यहीं आसपास घूम रहा है। उस दिन उन्हें किसी रिश्तेदार की शादी में पूरे परिवार के साथ जाना था। घर का बाहर से ताला लगाकर वे शादी में चले गए थे। जब वे रात के तीन बजे शादी में से वापस घर लौटे तो उन्होंने पिन्टू और उसके दूसरे साथियों के भौंकने की आवाज सुनी। वह डर रहे थे कि ये फिर मुझे परेशान करेंगे। उन्होंने दूर से ही अपने मकान की तरफ चुपके से देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मकान का मेन गेट थोड़ा सा खुला हुआ है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा कि एक चोर उनके घर से बैग चुराकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिन्टू डॉगी लहूलुहान हो गया है, पर उस चोर की पेंट को नहीं छोड़ रहा। साथी कुत्ते भी उसका घेरा बनाकर भौंक रहे हैं। यह नजारा देखते ही झम्मुक लाल ने तुरंत ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी गली वाले जाग गए और उस चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। झम्मुक लाल ने महसूस किया कि अगर आज यह पिन्टू डॉगी न आया होता तो चोर उसके घर का सफाया ही कर देते। पिन्टू पर उन्हें बहुत प्यार आया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज कराया। अब पिन्टू उनके घर का प्यारा डॉगी बन गया था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से हमला किया: इटली के 2 लोगों की मौत

कुवैत सिटी, एजेंसी। ईरान ने गुरुवार को कुवैत पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में इटली के 2 नागरिकों की मौत हो गई है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सेना ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था, लेकिन चार लोग उसके मलबे की चपेट में आ गए। एक पाकिस्तानी और एक कुवैती नागरिक भी घायल हुए हैं। इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मारे गए दोनों नागरिक एयर डिफेंस टेक्नीशियन थे। वे कुवैत में एक डिफेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और रडार सिस्टम के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुवैत में इटली की सैन्य मौजूदगी भी है। कुवैत में इटली के राजदूत लोरेंजो मोरिनी ने 4 नवंबर को बताया था कि वहां करीब 400 इटली के सैनिक तैनात हैं। इनमें से ज्यादातर एक एयरबेस पर तैनात हैं। राजदूत के मुताबिक, ईरान युद्ध के दौरान इटली के सैनिकों को कई हफ्तों तक बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में रहना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने कुवैत में अपनी तैनाती जारी रखी। इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। इजराइली सेना ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिका की मदद के बिना भी ईरान पर पूरी ताकत से सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। सेना के प्रवक्ता एफी डिफ्रिन ने सरकारी ब्रॉडकास्टर कान से कहा कि सेना हालात पर नजर रख रही है और किसी भी वक्त हमला कर सकती है।

सदी के अंत तक 140% तक बढ़ सकती हैं बिजली गिरने की घटनाएं

बर्लिन, एजेंसी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सदी के अंत तक धरती पर बादलों से जमीन पर गिरने वाली बिजली की घटनाएं मौजूदा स्तर के मुकाबले 76 से 140 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अलास्का जैसे ठंडे इलाकों में भी बिजली गिरने की घटनाओं में 594 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। यह खुलासा अर्थ्स फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में हुआ है। जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग की मदद से भविष्य में बिजली गिरने के संभावित पैटर्न का आकलन किया है। अध्ययन में तापमान, बारिश, नमी, वायुदाब, हवा की गति और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जैसे कारकों को शामिल किया गया। बिजली गिरने की एक बड़ी वजह धरती की सतह का गर्म होना और उससे वातावरण में पैदा होने वाली हलचल है। आकाशीय बिजली जंगलों में आग लगने, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बाधित करने का भी बड़ा कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं की चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्या तूफानों के शुरुआती चरण में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसा हुआ तो खुले मैदानों, खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। बदलते मौसमी मिजाज के साथ आसमान का व्यवहार भी बदल सकता है।

पिता ने अंतरिक्ष में सुनी बेटी के जन्म की खुशखबरी: धरती से सैकड़ों किमी दूर मनाया जश्न, आईएसएस पर हैं तैनात

वॉशिंगटन, एजेंसी। धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैनात एक पिता के लिए बेटी के जन्म की खबर किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जोशुआ कुट्रिक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन पूरा कर रहे हैं, इसी दौरान उनकी पत्नी हीदर कुट्रिक ने एक बेटी को जन्म दिया। अंतरिक्ष की दूरियों के बीच परिवार में आई इस नई खुशी ने उनके छह महीने के मिशन को एक यादगार व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने दंपती के घर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की। एजेंसी की ओर से जारी बयान में जोशुआ और हीदर ने कहा, हमारे बीच इतनी दूरी होने के बावजूद अपनी नन्ही परी के परिवार में आने पर हम एक-दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जोशुआ इतिहास में ऐसे केवल चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए अपने बच्चे के जन्म के मौके से दूर रहना पड़ा है। दंपती ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के दोबारा एकजुट होने का बेसब्री से इंतजार है। कुट्रिक का अंतरिक्ष मिशन बचपन से देखा गया उनका सपना था। दंपती ने कहा कि वे अपने बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी हैं। परिवार और समुदाय का सहयोग मिले।

ट्रंप का बड़ा बयान: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 'डील' करना चाहेंगे पुतिन

फ्लोरिडा, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 'एक डील करना चाहेंगे' और कहा कि उनकी प्राथमिकता जान के नुकसान को रोकना है. साथ ही उन्होंने रूसी लीडर के साथ रिश्ते बनाए रखने के अपने तरीके के बारे में भी बताया.

गुरुवार (लोकल टाइम) को फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो घर से अमेरिकी मिलिट्री के लोगों के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ थैंक्सगिविंग कॉल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह मॉस्को के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कहा कि पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बातचीत के प्रोसेस के लिए जरूरी है. पुतिन को पहले दोस्त बताने और बाद में रूसी मिलिट्री हमले पर अपनी बातों के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए, ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, बातें कही जा सकती है, लेकिन देखिए, आपको कुछ समझना होगा. हम एक डील करना चाहते हैं. हम मारना बंद करना चाहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं कह सकता हूं कि वह दोस्त नहीं है या इसके साथ नहीं है- ठीक है, मैं एक डील करना चाहता हूं. मुझे एक डील करनी है. वे हर महीने 25,000 लोगों को खो रहे हैं.' अपने तरीके को समझाते हुए, ट्रंप ने कहा कि पुतिन के प्रति दुश्मनी



दिखाने से समझौते की कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं. ट्रंप ने कहा, 'आप जानते हैं, उस सेटलमेंट में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास दो लीडर हैं जो सच में एक-दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है?' उन्होंने अमेरिकी पॉलिटिक्स में कथित रूसी दखल की जांच का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने 'फेक' जांच कहा, और फिर दोहराया कि पुतिन के साथ उनकी हालिया बातचीत सकारात्मक रही थी. तो, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. बॉटम लाइन यह है कि वह एक डील करना चाहेंगे, ' ट्रंप ने कहा. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि पुतिन फ्लोरिडा में अपने डोरल रिसॉर्ट में आने वाले जीन20 समिट में शामिल होंगे, ट्रंप ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता लेकिन वह रूसी लीडर का स्वागत करेंगे. 'मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह आना चाहते हैं, तो वह निश्चित रूप से आ सकते हैं. उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा.' ग्रुप ऑफ एट में रूस की पिछली मेंबरशिप को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा चाहते थे कि रूस को इस ग्रुप से हटा दिया जाए, और कहा कि इस फैसले से पुतिन की 'बहुत बेइज्जती' हुई. ट्रंप ने आगे कहा, 'जब वह ज8 के मेंबर थे, अगर वह मेंबर बने रहते -- प्रेसिडेंट ओबामा उन्हें बाहर करना चाहते थे, और अगर वह मेंबर बने रहते, तो शायद अभी यह जंग नहीं होती. जब ऐसा हुआ तो उनकी बहुत बेइज्जती हुई. और अब यह जी7 है, और सच कहूँ तो, हम बस रूस के बारे में बात करते हैं. मैंने कहा, 'वह यहाँ क्यों नहीं है?' उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ??है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो मुझे सच में पक्का यकीन है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो अभी यह जंग नहीं चल रही होती. फर्स्ट लेडी को लोगों को बाहर निकालने के लिए सीजफ़ायर करवाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती. कुछ लोग बहुत बूढ़े हैं, और लोगों को बाहर निकालते हैं.' गुरुवार (लोकल टाइम) को ट्रुथ सोशल पर एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने चीन में पुतिन के साथ अपनी हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी लीडर से यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट को आसान बनाने के लिए पूरे यूरोप में मिलिट्री अटैक वापस लेने की अपील की थी. ट्रंप ने लिखा, 'चीन में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान, मैंने इस बात पर बहुत समय बिताया कि मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन पूरे यूरोप के इलाकों के खिलाफ सभी मिलिट्री हमले वापस ले लें, इस उम्मीद में कि रूस और यूक्रेन के बीच एक डील हो सकती है, और जल्दी हो सकती है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सच में लगता है कि यह एक मजबूत संभावना है. हर महीने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, एक पूरा खून-खराबा, और यह सभी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी!' ट्रंप की यह बात मार-ए-लागो में नाटो (ह्लज्ञह) सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ उनकी मीटिंग के बाद आई. मीटिंग के बाद जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान में संघर्ष पर चर्चा की, जिसमें रूस को ऐसे कामों से बचने की जरूरत भी शामिल थी जो संघर्ष को बढ़ा सकते हैं और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत भी शामिल थी. ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ अपनी हाल की बातचीत के बारे में रूटे को जानकारी दी थी. यह डेवलपमेंट 19 नवंबर को ट्रंप, पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच शेनझेन, चीन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान हुई मीटिंग के बाद हुआ है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी नीतियों पर जताई गहरी नाराजगी, कहा– ट्रंप का ध्यान रूस से ज्यादा मध्य-पूर्व पर

कीव / वॉशिंगटन, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य सहायता में हो रही देरी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। कीव स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में बीबीसी की दक्षिणी और पूर्वी यूरोप संवाददाता सारा रेंसफ़ोर्ड को दिए एक विशेष इंटरव्यू में जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति में हो रही देरी के कारण यूक्रेन के नागरिकों की जान जा रही है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि युद्ध समाप्त करने के लिए जारी शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रशासन रूस पर पर्याप्त कूटनीतिक दबाव नहीं बना रहा है।

पुतिन को 'दोस्त' बताने पर भड़के जेलेंस्की; द्वितीय विश्व युद्ध के हिटलर से की तुलनागले मिलने की तस्वीर पर जताया ऐतराजः इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गले मिलते हुए अपनी तस्वीर साझा करने और उन्हें 'मेरा दोस्त' संबोधित करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जेलेंस्की ने कहा, 'बेशक, यह अमेरिकी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, लेकिन यह बेहद अजीब है। वह (पुतिन) हमलावर हैं और हत्यारे हैं... वह दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं।' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस कदम की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर को अपना मित्र बताने जैसी स्थिति से की। मध्य-पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने से यूक्रेन में निराशाः जेलेंस्की ने कहा कि यह बेहद अफसोसजनक और दुखद है कि अमेरिका ने अपना मुख्य ध्यान मध्य-पूर्व (मिडिल ईस्ट) पर केंद्रित कर दिया है और वहां के लोगों की अधिक मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर यूक्रेन के पास कई बड़े सवाल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ हुई तीखी बहस के बाद से ही जेलेंस्की अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं।

शांति वार्ता के बीच रूस अपने पुराने सख्त रुख पर कायम; ट्रंप ने जताई समझौते की उम्मीदअमेरिकी दूतों की भूमिका और रूस का रुखः वर्तमान में ट्रंप के दो विशेष दूत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने तथा बड़े पैमाने पर हो रही जनहानि को रोकने के लिए शांति समझौते पर मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि, राजनयिक हलकों में कई बार यह महसूस किया जा रहा है कि अमेरिकी दूत यूक्रेन के बजाय रूस के दृष्टिकोण से अधिक सहमत नजर आते हैं। दूसरी ओर, रूस के ताजा सार्वजनिक बयानों से संकेत मिलता है ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का बयानः इसी बीच, गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर कहा कि पिछले सप्ताह चीन में पुतिन के साथ हुई।

बांग्लादेश में शेख हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव समेत तीन गिरफ्तार

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव समेत तीन लोगों को गुरुवार तड़के राजधानी ढाका में गिरफ्तार किया गया. सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी. सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव केएम शखावत मून और दो अन्य लोगों को ढाका के धानमंडी-27 इलाके से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों में पूर्व उपायुक्त मोहम्मद इलियास हुसैन और आयकर अधिवक्ता सूफी मोहम्मद अल मामून शामिल हैं. 'द डेली स्टार' अखबार के अनुसार, जातीयतावादी छात्र दल (जेसीडी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तीनों को ढाका के धानमंडी इलाके में पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. जेसीडी सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का छात्र संगठन है. मोहम्मदपुर थाने के ड्यूटी अधिकारी उपनिरीक्षक मसूदुर रहमान ने बताया कि पुलिस तीनों को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है. इस बीच, हसीना की अगले महीने प्रस्तावित वापसी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है. सीमा सुरक्षा बल के 108 प्लाटून तैनात किए गए हैं, जिनमें से 56 हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात हैं. हसीना की संभावित वापसी को लेकर पिछले कुछ सप्ताह में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं. इनमें ट्रेन, बस और बैंकों को आग लगाने की घटनाएं भी शामिल हैं. हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के कारण उनकी सरकार गिरने के बाद ढाका छोड़कर भारत चली गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं. पुलिस ने हालिया हिंसक घटनाओं के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है. सुरक्षा बढ़ाने के पीछे आशंका है कि हसीना के समर्थक आने वाले दिनों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं तेज कर सकते हैं. प्रतिबंधित अवामी लीग ऑनलाइन माध्यमों से 29 और 30 नवंबर को लॉकडाउन कार्यक्रम का प्रचार कर रही है।

अमेरिका में तूफान से 9 लाख घरों की बिजली गुल:1800 फ्लाइट्स लेट, 400 रद्द

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में तूफान से तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण 9 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। वहीं, 1800 फ्लाइट्स लेट हुईं और 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी तट पर समुद्र का पानी 14 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच सकता है। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। पूर्वी तट पर 'नॉरईस्टर' नाम का तूफान आगे बढ़ रहा है। इसके चलते न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं।



थैंक्सगिविंग के लिए यात्रा कर रहे लोगों की परेशानी बढ़ी : खराब मौसम के कारण लाखों लोगों की यात्रा प्रभावित हो रही है। थैंक्सगिविंग अमेरिका का बड़ा त्योहार है। इस दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। ऐसे में हवाई सफर में देरी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

इसका असर सिर्फ हवाई सफर पर ही नहीं, बल्कि त्योहार के कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। न्यूयॉर्क में होने वाली मशहूर थैंक्सगिविंग डे परेड को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। यह परेड का 100वां साल है और इसके इतिहास में पहली बार इसे टालना पड़ा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तूफान के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। परेड की आयोजक कंपनी मैसीज ने कहा कि लोगों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

तेज लहरों से तटीय ढांचों को नुकसान : अमेरिका के पश्चिमी तट पर समुद्र में उठ रही तेज लहरों ने किनारे बने कई ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। सैन डिएगो के आसपास समुद्र का पानी पुराने रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। इससे आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं, पूर्वी तट पर 2012 में आए सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद समुद्र का जलस्तर सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के कारण बिजली की लाइनें टूटने और सप्लाई बंद होने का खतरा बना हुआ है। मौसम का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं है।

अमेरिका के मध्य हिस्सों में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इससे कई इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। इसके अलावा पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके में बुधवार रात से बारिश और तेज हवाओं का एक और दौर शुरू होने की आशंका है। यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को अभी खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद कम है। नॉरईस्टर अमेरिका के पूर्वी तट पर आने वाला तेज तूफान है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दौरान हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से चलती हैं।

बांग्लादेशी मंत्री बोले- दिसंबर में सर्दी आएगी, हसीना नहीं : सरकार ने पूर्व क्रूरक के गृह-जिले का फंड रोका

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। हसीना ने 16 दिसंबर को देश लौटने की बात कही है। इस पर विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने तंज कसते हुए कहा कि दिसंबर में सिर्फ सर्दी आएगी, हसीना नहीं। इस बीच, सरकार ने शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में विकास के लिए मिलने वाला पैसा रोक दिया है। जिले की कम से कम 5 ट्रेनें बंद हैं और दो पुलिस थानों में भी कामकाज ठप है।

अवामी लीग ने आज से देशभर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। पार्टी ने हसीना की वापसी, राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रोक हटाने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई समेत 8



मांगें रखी हैं। सरकार ने भी हालात को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

हिंसा के बाद सरकार ने रोकी आर्थिक मदद : गोपालगंज में 15 नवंबर को अवामी लीग के सैकड़ों समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और क्रूरक नेताओं की संपत्तियों में आग लगा दी थी। इसके बाद तारिक रहमान की क्रूरक सरकार ने जिले की स्थानीय निकायों को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने का फैसला किया।

ढाका के अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने जिला परिषद, उपजिला परिषद, नगरपालिकाओं और यूनियन परिषदों को मिलने वाली आर्थिक मदद की तीसरी किस्त रोक दी है। यह किस्त जनवरी से मार्च 2027 के बीच मिलनी थी। आमतौर पर इन निकायों को साल में चार किस्तों में पैसा दिया जाता है। बीबीसी के मुताबिक, जिले के विकास कार्यों के लिए पहले से मंजूर करीब 5 अरब टका की रकम भी रोक दी गई है। हसीना की वापसी से बढ़ा तनाव बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ दिन पहले अपनी वतन वापसी की तारीख बताई थी।

उन्होंने इसके लिए तारिक रहमान सरकार से विमान भेजने की मांग की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने बताया कि हसीना सरकारी एयरलाइन विमान बांग्लादेश की फ्लाइट से दिल्ली से ढाका लौटना चाहती हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों का संगठन था।

पाकिस्तान में इस साल 84 अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं का अपहरण धर्म परिवर्तन कराया गया : रिपोर्ट



इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जारी अत्याचारों को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी' (वीओपीएम) के अनुसार, इस साल के पहले 10 महीनों में कम से कम 84 अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों का अपहरण किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उनकी शादी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ितों में 49 ईसाई और 35 हिंदू लड़कियां एवं महिलाएं शामिल हैं। इन 84 पीड़ितों में से 43 नाबालिग थीं, जबकि छह लड़कियों की उम्र 14 साल से भी कम थी। संगठन ने बताया कि सबसे ज्यादा मामले पंजाब प्रांत से सामने आए, जहां 47 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 18 मामले सिर्फ लाहौर के थे। वहीं सिंध में 36 मामले दर्ज हुए, जबकि बलूचिस्तान में एक मामला सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के 515 मामले दर्ज किए गए। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। वीओपीएम ने कहा, 'हर आंकड़े के पीछे एक ऐसी बच्ची है, जिसे उसके घर से छीन लिया गया। उससे उसकी मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन कराया गया और ऐसे व्यक्ति से शादी कराई गई जिसे उसने कभी नहीं चुना। उसके माता-पिता उसे खोजते रहते हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जाती है।

संगठन के अनुसार, कई परिवार शिकायत तक दर्ज नहीं कराते, क्योंकि उन्हें बदले की कार्रवाई का डर रहता है और उन्हें भरोसा नहीं होता कि व्यवस्था उनकी रक्षा कर पाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह खामोशी इस समस्या की वास्तविक गंभीरता को छुपा देती है और यह भी दिखाती है कि पीड़ितों का सरकारी व्यवस्था पर कितना कम भरोसा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए संगठन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अधिकारी इन अपराधों को रोकने और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं।

ट्रंप की पहल को नजरअंदाज करने के बाद किम ने और परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया

सियोल , एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों का दौरा किया और अधिक परमाणु हथियार बनाने का आह्वान किया. इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया एशिया यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करने की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया था.

किम के इस बयान से एक बार फिर संकेत मिलता है कि वह अपने लगातार विकसित हो रहे परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. साथ ही, वह परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उत्तर कोरिया की स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं.

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने गुरुवार को बताया कि किम ने परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले दो कारखानों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जबकि दूसरे का विस्तार किया जा रहा है. केसीएनए की ओर से जारी तस्वीरों में किम और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ऐसी मशीनों की कतारों के बीच चलते नजर आए, जो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उच्च संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन में प्रयुक्त सेंट्रीफ्यूज प्रतीत हो रही थीं. उन्होंने उन कक्षों का भी दौरा किया, जहां कथित तौर पर परमाणु हथियारों के मुखास्त्र



प्रदर्शित किए गए थे. कुछ तस्वीरों को धुंधला कर दिया गया था.

उत्तर कोरिया ने 2010 में अपने प्रमुख योंगब्योन परमाणु परिसर का दौरा करने आए अमेरिकी विद्वानों को यूरेनियम संवर्धन केंद्र दिखाने के बाद कुछ ही मौकों पर ऐसे केंद्रों का खुलासा किया है. उत्तर कोरिया ने यह नहीं बताया कि किम ने इस सप्ताह जिन परमाणु सामग्री उत्पादन कारखानों का दौरा किया, वे कहां स्थित हैं. केसीएनए के मुताबिक, किम ने कहा कि उनका हालिया निरीक्षण दौरा ''कोरियाई प्रायद्वीप की ओर हर पल बढ़ रहे परमाणु खतरों'' के मद्देनजर उत्तर कोरिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा था केसीएनए के अनुसार, किम ने कहा, ''हमारे पास परमाणु हथियार होने की वैधता और आवश्यकता तथा हमारी परमाणु क्षमता को गुणवत्ता एवं संख्यात्मक रूप से मजबूत करने की दिशा में जारी प्रयास एक ऐसी वास्तविकता हैं, जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता.'' किम ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम मारक क्षमता वाले परमाणु हथियारों को और विकसित करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे हथियारों की तैनाती बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर कोरिया ''सबसे खतरनाक शत्रु देश के साथ सीमा साझा करने की अपरिहार्य वास्तविकता'' का सामना कर रहा है. उनका इशारा दक्षिण कोरिया की ओर था.

इस घटनाक्रम के बीच दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु हथियारों के संबंध में किम की टिप्पणियों को गंभीरता से लेता है. मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन के तहत दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह सैन्य रूप से तैयार है. दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' ने केसीएनए द्वारा दी गई उत्तर कोरिया के परमाणु प्रतिष्ठानों संबंधी जानकारी का विश्लेषण साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका की गोपनीय जानकारी है. ट्रंप ने पिछले सप्ताह एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा के दौरान किम के साथ कूटनीतिक वार्ता बहाल करने की अपनी इच्छा दोहराई थी. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हो सकी और उत्तर कोरिया ने ट्रंप की पेशकश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शोपियां में तीन संदिग्ध गिरफ्तार, हथगोले और पोस्टर बरामद

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को आतंकवादियों के तीन कथित ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, तीन मोबाइल फोन, एके राइफल के 20 कारतूस और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पांच पोस्टर बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने नरवाव और रावलपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान तीन संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और मामले में आगे की जांच जारी है।

5 साल में 9.25 लाख भारतीयों ने बदली अपनी नागरिकता

● सबसे ज्यादा कनाडा की नागरिकता ली

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के नागरिक न केवल देश के भीतर, बल्कि दुनियाभर के तमाम मुल्कों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी बीच नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते पांच वर्षों (2020-2024) के दौरान करीब 9.25 लाख भारतीयों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा ओईसीडी की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2026 रिपोर्ट में सामने आया है, जो कि इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या 2015-2019 की पिछली पांच वर्षीय अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है, जब 6,54,821 भारतीयों ने इन देशों की नागरिकता ली थी। इस मामले में, भारत पूर्व राष्ट्रीयता के आधार पर सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने मैक्सिको (5,90,248) और सीरिया (5,88,219) जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। जहाँ एक ओर सीरियाई नागरिकों द्वारा नागरिकता हासिल करने के मामलों में लगभग पांच गुना वृद्धि देखी गई है, वहीं चीनी नागरिकों की संख्या में 11.9 प्रतिशत की कमी आई है।

ओईसीडी समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के कई देश सहित कुल 38 सदस्य देश शामिल हैं। भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने में कनाडा सबसे आगे रहा है, जिसने 2024 में सिर्फ 87,320 भारतीयों को अपनी नागरिकता दी। 2020 से 2024 के बीच की अवधि में लगभग 2.61 लाख भारतीय कनाडा के नागरिक बने हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद अमेरिका ने 48,820 भारतीयों को नागरिकता देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 28,969 भारतीयों को नागरिकता प्रदान कर तीसरा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में कुल 2,30,337 भारतीय नागरिकों ने ओईसीडी सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की, जो 2023 में 2,24,630 थी, जो इस बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

रैगिंग पड़ी महंगी : केजीएमयू के 38 छात्र निलंबित

लखनऊ, एजेंसी। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में रैगिंग के आरोप में 38 एमबीबीएस छात्रों को निलंबित किया है। उन्हें तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है, साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना, एक साल की छात्रवृत्ति पर रोक और हॉस्टल से निष्कासन जैसी कठोर सजाएं भी दी गई हैं।

एंटी-रैगिंग सेल की जांच में सामने आया कि ये सीनियर छात्र रात 12 से 2 बजे तक जूनियर छात्रों को वीडियो कॉल पर जगाकर जबरन डांस करते थे। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता था। जूनियर्स को सीनियर्स के सामने सिर झुकाकर प्रणाम महोदय और प्रणाम मैडम कहने पर मजबूर किया जाता था। यह मामला 16 नवंबर को केजीएमयू कैंपस में रैगिंग का वीडियो सामने आने के बाद उछला था। एंटी-रैगिंग सेल ने जांच शुरू की और 26 नवंबर को कुलपति ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को मंजूरी दी।

परिसीमन बिल: राहुल गांधी ने संभाली कमान, विपक्षी एकता पर जोर

कांग्रेस बोली- मौजूदा सीटों की संख्या बरकरार रहे, महिला आरक्षण भी वर्तमान लोकसभा सीटों के आधार पर लागू हो

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। संसद में विधेयक पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ने इसके विरोध की रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की संसदीय रणनीति बैठक में स्पष्ट किया कि पार्टी परिसीमन विधेयक को रोकने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी और सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि विपक्षी गठबंधन का कोई दल सामूहिक रूप से तय रुख से अलग जाता है तो उसके साथ राजनीतिक संबंधों की समीक्षा की जा सकती है।

कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक कल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने डीएमके, समाजवादी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को विपक्षी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बताया।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट परिसीमन विधेयक के पक्ष में मतदान करता है तो कांग्रेस को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन के किसी घटक के सामूहिक फैसले से पीछे हटने की स्थिति में उसके साथ पहले की तरह काम करना कठिन होगा।

सांसदों को विधेयक की प्रतियां नहीं मिलने का आरोप

कांग्रेस ने सरकार पर प्रस्तावित विधेयकों को लेकर सांसदों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक, 30 नवंबर को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े अन्य विधेयक पेश किए जाने हैं, लेकिन सांसदों को अभी तक उनकी प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बड़े संवैधानिक बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि



कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या बरकरार रखी जाए। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण भी वर्तमान लोकसभा सीटों के आधार पर लागू किया जाए। इसके साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक नहीं बदला जाना चाहिए।

दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा में रही शरद गुट की बहानेबाजी

● इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सियासत के दिखे कई रंग

नई दिल्ली, एजेंसी। परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी गठबंधन ने अपनी रणनीति बनाने के लिए शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे बैठक बुलाई। ये बैठक शुरु होती इससे पहले सियासत कई रंगों में रंगी दिखाई दी। शरद पवार गुट की एनसीपी की बहानेबाजी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे दिन कहीं न कहीं इसकी चर्चा होती ही रही। दरअसल, पहले सांसद निलेश लंके को इस बैठक में एनसीपी-एसपी का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन उन्होंने किले की सफाई अभियान के लिए तोरणा किले पर जाने का हवाला दिया है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने भी बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। सुले ने कहा था कि वह 30 नवंबर को दिल्ली आएंगी और सीधे संसद सत्र में शामिल होंगी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि यह इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

यह बिल लोकसभा सीटों की संख्या में सभी राज्यों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान करता है। सरकार अगले हफ्ते इसे संसद में पेश कर सकती है। परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग नामक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय को सौंपा जाता है। भारत में परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत अब तक चार परिसीमन आयोग (1952, 1963, 1973 और 2002 में) गठित किए गए हैं। विपक्षी दल परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का हवाला देते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई है। विपक्षी दलों को संदेह है कि चुनावी लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल पर 2029 के आम चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए देश का चुनावी नक्शा फिर से तैयार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि, सरकार ने इन आशंकाओं को सिरे से खारिज किया है।

पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में पहुंचा, मप्र के करौंदी में पारा 6.1डिग्री गिरा

● भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। पहाड़ों पर पारा माइनस में पहुंच गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में तापमान -10डिग्री और केदारनाथ में -8डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित करौंदी में पारा 6.1डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को शीतलहर का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में 30 नवंबर तक शीतलहर चलेगी। इस दौरान पारा 4 से 6 डिग्री रह सकता है। वहीं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का अलर्ट है। कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में पारा गिरकर -2डिग्री पर पहुंच गया। घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जाने के कारण सरकार ने स्कूलों में फरवरी तक विंटर वेकेशन घोषित कर दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे का अलर्ट है। बाकी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। दिल्ली की हवा 13वें दिन भी 'खराब' कैटेगरी में रही। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 226 दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा 15 नवंबर से लगातार 'खराब' कैटेगरी में बनी हुई है। सुबह के आंकड़ों के मुताबिक पीएम2.5 प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण रहा।



हमारी दो चिंताओं का समाधान हो जाएगा, यह बिल बुनियादी चिंता का समाधान नहीं करता

परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने केंद्र सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल

नई दिल्ली , एजेंसी । देश के पूर्व वित्तमंत्री और राज्य सभा से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने परिसीमन बिल को लेकर एक्स पर पोस्ट में लिखा- प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है। लोकसभा की कुल सीटों में प्रत्येक राज्य के मौजूदा आनुपातिक हिस्से को 25 सालों के लिए फ्रीज करने से हमारी दो चिंताओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि, यह विधेयक पहली और सबसे बुनियादी चिंता का समाधान नहीं करता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिदंबरम ने कहा कि कुल सीटों में प्रत्येक राज्य का आनुपातिक हिस्सा अहम है, लेकिन सीटों की वास्तविक संख्या भी मायने रखती है। इसके अलावा, लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ने से प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होगा। इससे सरकार को राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में मनमानी फेरबदल करने की खुली छूट मिल जाएगी। जैसा कि सरकार ने असम और जम्मू-कश्मीर में किया था। इस तरह सीटों का मनमाना बंटवारा बड़ा खतरा है।चिदंबरम ने एक्स पोस्ट के आखिर में लिखा- सरकार ने अभी तक हमारे मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या में ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता?

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे परिसीमन नहीं, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करार दिया। झा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर बाधा डालने के सत्तारूढ़ गठबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है।



सोमवार को विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसके सवाल पर झा ने कहा कि संसद का मानसून सत्र कभी स्थगित नहीं किया गया था। तकनीकी रूप से यह अब भी मानसून सत्र ही है, जिसे शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि सरकार इस तरह के हथकंडों से क्या हासिल करना चाहती है? इसे परिसीमन नहीं कहिए। यह वास्तव में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, जिसे बीजेपी असम में पहले ही आजमा चुकी है।

सीमा को लेकर चीन ने दिया दोहरा बयान, विशेषज्ञों ने बताया 'मीठी छुरी' चलाने जैसा

चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत या 'जंगनान' कहता आया है

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चेन शी ने भारत-चीन सीमा को लेकर दोहरा बयान दिया, जिसे विशेषज्ञों ने 'मीठी छुरी' चलाने जैसा बताया। एक तरफ बीजिंग ने कहा है कि भारत-चीन सीमा पर हालात सामान्य तौर पर स्थिर हैं और दोनों देश शांति बनाए रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना पुराना और बेबुनियाद दावा दोहराया। चेन शी ने अपने मनगढ़ंत राज्य 'जंगनान' का नाम लेते हुए कहा कि वे अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देते। यह बयान चीन की उस विस्तारवादी कहानी का हिस्सा है, जिसमें वह सीमा के हर इलाके को अपना बताता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ शांति और स्थिरता की बात करना और दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश करना, ड्रैगन की यह दोहरी चाल उसके असली इरादों को बेनकाब करती है। जब चीन कहता है कि सीमा पर हालात स्थिर हैं और बातचीत चल रही है, तो यह सकारात्मक लगता है, लेकिन जैसे ही वह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने और उसे न मानने की बात करता है, तो उसकी 'शांति की इच्छा' पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वाकई हालात स्थिर हैं और दोनों देश शांति चाहते हैं, तो फिर बीच-बीच में इस तरह के भड़काऊ और दावेदारी वाले बयान की जरूरत क्यों पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का यह रवैया दशकों पुराना है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत या 'जंगनान' कहता आया है। यह सब चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह सीमा इलाकों में अपना दबदबा दिखाना चाहता है। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित इलाका नहीं, बल्कि देश का अभिन्न हिस्सा है। भारत सरकार और भारतीय सेना हर मंच पर यह बात साफ और सख्त शब्दों में कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और किसी के कहने या न मानने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती।

जानकारों का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की यह बेचैनी और बयानबाजी उसकी अपनी असुरक्षा और दबाव बनाने की नीति से जुड़ी है। हिमालयी क्षेत्र में



भारत की बढ़ती ताकत, सीमावर्ती इलाकों में बेहतर होती सड़क और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और दुनिया के मंचों पर भारत की मजबूत होती स्थिति चीन को रास नहीं आती। अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और चीन के लिए हमेशा एक संवेदनशील बिंदु रहा है। जब भी चीन को लगता है कि भारत सीमा पर मजबूत हो रहा है या कूटनीति में आगे निकल रहा है, तब वह इस तरह के बयानों के जरिए अपनी दावेदारी जताकर दबाव बनाने की कोशिश करता है।

सीजेपी ने उठाए सवाल कहा- लो अब ज्ञानेश तय करेंगे चुनावी नक्शा!

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि परिसीमन विधेयक पारित हो जाता है, तो ज्ञानेश कुमार पूरे भारत की चुनावी सीमाओं को दोबारा तय करने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे और सवाल किया, क्या इसे निष्पक्ष परिसीमन कहा जा सकता है?

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के अनुसार, कानून लागू होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे। इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। इस प्रस्ताव के तहत ज्ञानेश कुमार आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं, जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण सामूहिक रूप से करेगा। यह आयोग लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगा। आयोग की सहायता के लिए राज्यों से लोकसभा सांसदों और विधायकों को सहयोगी सदस्य के तौर पर जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है। ज्ञानेश कुमार पिछले कुछ महीनों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में अन्य चुनाव आयुक्तों द्वारा मतदाता सूची से जुड़े कामकाज और निगरानी व्यवस्था पर आपत्ति दर्ज कराने का दावा किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस पृष्ठभूमि में परिसीमन प्रक्रिया में उनकी संभावित भूमिका को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या और अन्य मानकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के प्रतिनिधित्व में संतुलन कायम करना है। हालांकि, भारत में इसे लेकर राजनीतिक मतभेद रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। वहीं, विपक्षी दल परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात या जेरीमेंडरिंग की आशंका जताते रहे हैं, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इससे पहले, सरकार अप्रैल में परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित विधायी पैकेज पेश किया था, लेकिन वह लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका था। अब नए प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 650 तक करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50 फीसदी तक सीटों की वृद्धि संभव है। साथ ही, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को 2051 तक सुरक्षित रखने का भी प्रस्ताव है, ताकि जनसंख्या को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को कुछ हद तक कम किया जा सके। परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने की बात सामने आई है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार इन नए विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे में परिसीमन आयोग की प्रस्तावित संरचना, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण की प्रक्रिया आने वाले दिनों में देश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनने वाली है।

महिला आरक्षण: मायावती ने किया स्वागत, एससी/एसटी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग

लखनऊ , एजेंसी । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए अलग से कोटे का प्रावधान करने की जोरदार मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा शुरू से ही महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राजनीति में उचित भागीदारी की प्रबल पक्षधर रही है और 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग करती रही है। उन्होंने जोर दिया कि यह कदम और भी न्यायपूर्ण तथा ऐतिहासिक होता यदि सदियों से शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रही, खासकर एससी और एसटी समाज की महिलाओं के लिए, इसी व्यवस्था में अलग से आरक्षण दिया जाता। उनका तर्क था कि ऐसा करने से इन वर्गों की महिलाओं को चुनावी राजनीति में समान मौका और उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता।

चीन की मदद से पाकिस्तान बढ़ा रहा अंतरिक्ष निगरानी क्षमता

सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने चेताया और बोले- भारत को 52 सैटेलाइट कार्यक्रम तेज करने की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी । भारत की सुरक्षा चुनौतियां अब जमीन, समुद्र और हवा के साथ-साथ अंतरिक्ष तक फैल चुकी हैं। चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता और पाकिस्तान को मिल रही संभावित तकनीकी मदद के बीच भारत को अपनी अंतरिक्ष आधारित निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान की खुफिया, निगरानी और लक्ष्य पहचान क्षमता बेहतर हो सकती है। इसके मद्देनजर भारत अपने- 52 निगरानी उपग्रहों वाले स्पेस बेस्ड सर्विलांस (एसबीएस-3) कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।

नई दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आयोजित 'विमर्श ऑन फ्यूचर ऑफ वारफेयर एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू कंडक्ट मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस' कार्यक्रम में सीडीएस ने अंतरिक्ष आधारित युद्ध की बदलती चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता चीन की मदद से बढ़ रही है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष संगठन सुपार्को भी अपनी स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने में जुटा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को इस संभावना को ध्यान में रखना चाहिए कि तुर्किये भी पाकिस्तान की मदद कर सकता है। जनरल सुब्रमणि के मुताबिक, चीन की आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस) और पीएनटी (पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग) क्षमताओं का लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है। इससे वह भारतीय सैन्य ठिकानों, सीमावर्ती गतिविधियों और सैन्य संसाधनों की निगरानी में बेहतर स्थिति हासिल कर सकता है।

एसबीएस-3 में 52 निगरानी उपग्रह

भारत के एसबीएस-3 कार्यक्रम के तहत 52 निगरानी उपग्रह तैनात करने की योजना है। इनमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्टिकल सेंसर तस्वीरों के जरिए निगरानी करेंगे, जबकि एसएआर आधारित उपग्रह बादल और अंधेरे जैसी परिस्थितियों में भी जमीन की निगरानी करने में सक्षम होंगे। इन्हें लो-अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और कार्यक्रम को मूल रूप से 2029 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीडीएस ने कहा कि आधुनिक युद्ध अब थल, जल और वायु तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी सैन्य अभियानों के अहम हिस्से बन चुके हैं। भारत इसी बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रहा है।